नई दिल्ली
बुधवार
18 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 75
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

DELHIN/2014/58158



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को करेंगे...पेज-05

धोनी ने आईपीएल को कहा अलविदा, अब चेन्नई...पेज-06

एक नजर

सीतारमण ने उद्योग प्रतिनिधियों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के साथ कीं प्री-बजट परामर्श बैठक

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2027-28 के संबंध में विनिर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ तीसरी और एमएसएमई क्षेत्र और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों के साथ चौथी 'प्री-बजट परामर्श' बैठक की। मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सचिवों के साथ-साथ भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। इससे पहले केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए सरकार की तैयारियों के तहत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ तीसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की भी अध्यक्षता की। इस वार्षिक बैठक का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव जुटाना है, ताकि सरकार को केंद्रीय बजट 2027-28 की प्राथमिकताओं और प्रस्तावों को तैयार करने में मदद मिल सके। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), खान मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को सीतारमण ने बजट-पूर्व परामर्श के पहले एवं दूसरे दौर की बजट पूर्व बैठकों की अध्यक्षता की। इसमें आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय बजट 2027-28 के 1 फरवरी, 2027 को पेश किए जाने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण, 29 जनवरी या 31 जनवरी, 2027 को पेश किए जाने की संभावना है।

चक्रवाती तूफान अकवान हुआ सक्रिय, शुक्रवार को आंध्र तट से टकराने की आशंका

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अकवान' लगातार उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके आज शाम तक गंभीर चक्रवाती तूफान और गुरुवार सुबह तक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। यह तूफान शुक्रवार, 20 नवंबर की दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के यनम के तटों को नेल्लोर एवं टुनी के बीच पार कर सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक चक्रवात पिछले छह घंटों के दौरान तीन किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। मंगलवार सुबह 5:30 बजे यह दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 12.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 85.7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर केंद्रित था। इस समय यह चेन्नई से लगभग 610 किलोमीटर पूर्व, श्रीलंका के त्रिंकोमाली से 630 किलोमीटर उत्तर-पूर्व, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से 660 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम से 670 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और ओडिशा के गोपालपुर से करीब 790 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। आईएमडी के मुताबिक तूफान के 20 नवंबर की दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यनम तट के बीच नेल्लोर और टुनी के मध्य समुद्र तट से टकराने का पूर्वानुमान है। इस दौरान इसकी निरंतर हवा की गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि तेज झोंकों के साथ हवा की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है।

भारत और आसियान आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाएंगे, शुरुआती चेतावनी प्रणाली और संयुक्त अभ्यास पर जोर



नई दिल्ली,एजेंसी। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने, भूकंप, सुनामी, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने तथा आपात स्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव अभियान चलाने की क्षमता बढ़ाने पर सहमति जताई है। मनीला में मंगलवार को आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के अवसर पर जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन के पूरे चक्र में सहयोग गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आपदा रोकथाम, तैयारी, राहत एवं बचाव कार्य और पुनर्वास को शामिल किया गया है।

संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और आसियान की आपदा प्रबंधन समिति तथा एएचएफ केंद्र के बीच नियमित विचार-विमर्श को मजबूत किया जाएगा। इसके माध्यम से आपदा प्रबंधन से जुड़े साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर संयुक्त कार्रवाई की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। दोनों पक्ष भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणालियों पर सहयोग बढ़ाएंगे। इसके तहत स्वैच्छिक आधार पर उपग्रह आंकड़ों, भूकंपीय निगरानी संबंधी सूचनाओं और मौसम पूर्वानुमानों को साझा करने पर जोर दिया गया है। आपदा जोखिम के आकलन, निगरानी और पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष आधारित आंकड़ों एवं तकनीक के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वक्तव्य में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए नियमित प्रशिक्षण, अनुकरण अभ्यास और आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों के आदान-प्रदान की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई गई है। प्रभावित देश के अनुरोध या उसकी सहमति से मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री की त्वरित तैनाती को भी सुगम बनाया जाएगा। दोनों पक्षों ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में आसियान सदस्य देशों तथा भारत के सशस्त्र बलों और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति जताई। यह सहयोग एडीएमएम-प्लस ढांचे के तहत संबंधित एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र के अनुरूप होगा। इसमें नागरिक प्रशासन की प्राथमिक भूमिका और सैन्य संसाधनों के इस्तेमाल को अंतिम विकल्प के रूप में रखने की बात कही गई है। संयुक्त वक्तव्य में आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के अनुभवों तथा पर्यावरण के अनुकूल उपायों को साझा करने पर भी जोर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की तैयारियों और पुनर्वास में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों तथा दिव्यांगजनों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने और संवेदनशील समूहों की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है।

आपदा प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग और बड़े आंकड़ों के विश्लेषण के सुरक्षित, जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके माध्यम से आपदा जोखिम का आकलन, शुरुआती चेतावनी और राहत कार्यों के समन्वय को बेहतर बनाने का प्रयास होगा। दोनों पक्षों के अनुसंधान संस्थानों के बीच आपदा प्रतिरोधी तकनीकों और बुनियादी ढांचे के मानकों पर सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां और तकनीकी आदान-प्रदान की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और आसियान का एएचएफ केंद्र इस दिशा में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे। संयुक्त वक्तव्य में संबंधित आसियान निकायों और भारत की समकक्ष एजेंसियों को 2026-2030 की आसियान-भारत कार्ययोजना के अनुरूप इस सहयोग को लागू करने के लिए ठोस गतिविधियों की पहचान करने और मौजूदा व्यवस्थाओं के तहत प्रगति की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि भारत और आसियान के देश भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, अत्यधिक गर्मी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक एवं जलवायु जनित आपदाओं के जोखिम का सामना करते हैं। दोनों पक्षों ने माना कि इन आपदाओं का सबसे अधिक प्रभाव कमजोर और संवेदनशील परिस्थितियों में रहने वाले लोगों पर पड़ता है।

मोदी की फिलीपींस यात्रा: भारत-आसियान समुद्री सहयोग योजना, साइबर प्रशिक्षण और मुफ्त ई-वीजा सहित कई पहल की घोषणा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 16-17 नवंबर की फिलीपींस यात्रा के दौरान भारत-आसियान समुद्री सहयोग, साइबर सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज और युवा संपर्क सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की पहल की गई। आसियान देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा और नालंदा विश्वविद्यालय में उनके लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाने की भी घोषणा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी यात्रा के परिणामों की सूची के अनुसार, 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में दीर्घकालिक भारत-आसियान समुद्री सहयोग योजना की घोषणा की गई। इसके तहत संपर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, समुद्री क्षेत्र की निगरानी और नाविकों की सुरक्षा के क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा। क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान और भारत-आसियान अंतरिक्ष हैकाथॉन आयोजित करने की भी पहल की गई है। इसके अलावा खनन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।

सुप्रीम कोर्ट में इंडी गठबंधन के नेताओं की याचिका पर सुनवाई टली, 9 दिसंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ी विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

लंच के बाद के सत्र में एक अन्य आंशिक रूप से सुने गए मामले की सुनवाई और दोपहर 3:30 बजे एक स्पेशल बेंच के बैठने के कारण इस मामले को स्थगित कर दिया गया। इंडी गठबंधन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय को बताया कि राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने एक नई अर्जी दाखिल की है। इसके तहत निर्वाचन आयोग से एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। इंडी गठबंधन के वकीलों ने इस नई अर्जी पर तुरंत नोटिस जारी करने की मांग की लेकिन निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और मनिंदर सिंह ने प्रारंभिक सुनवाई से पहले नोटिस जारी करने का विरोध किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीश 9 दिसंबर को मुख्य याचिकाओं के साथ-साथ इन 48 सवालों वाली अर्जी पर भी सुनवाई करेगा और उचित आदेश पारित करेगा। याचिकाकर्ताओं की अर्जी में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी समेत आयोग के आईटी महानिदेशक को उनके सवालों के जवाब अलग-अलग हलफनामों के जरिए देने का निर्देश दिया जाए।

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उप्र सरकार की अपील खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने सपा नेता की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की उन अपीलों को भी स्वीकार कर लिया, जो उन्हें ऐसी ही राहत न मिलने के खिलाफ दायर की गई थीं। यह मामला 3 जनवरी 2019 का है, जब रामपुर से मौजूदा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे। इनमें एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से बनवाया गया।

दिल्लीः ज्वाला नगर में रेलवे भूमि पर पुरानी इमारत ढही, दो लोगों की मौत, सात का रेस्क्यू

सद्भावना टुडे, वरिष्ठ संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के ज्वाला नगर क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां वार्ड संख्या 216 (झिलमिल) के अंतर्गत मुकेश नगर में रेलवे की अतिक्रमित भूमि पर स्थित एक पुरानी इमारत अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। घायलों को उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल और डॉ. हेडगेवार अस्पताल भेजा गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे वाली इमारत रेलवे लाइन से लगभग 24 मीटर की दूरी पर स्थित थी। भवन करीब 40 से 50 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। इसमें भूतल, प्रथम मंजिल और आंशिक रूप से निर्मित द्वितीय मंजिल थी। इमारत का अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग गज था। बताया गया है कि भवन की छत लाल पत्थर की स्लैब और लोहे के गर्डर से निर्मित थी। पहली मंजिल की लाल पत्थर की स्लैब वाली छत तथा आंशिक रूप से निर्मित दूसरी मंजिल को सहारा देने वाले लोहे के गर्डर ढहने के कारण पूरी



इमारत मलबे में तब्दील हो गई। घटना की सूचना सुबह करीब 10:25 बजे मिली। सूचना मिलते ही एमसीडी, जिला प्रशासन, एसडीएम, एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) और दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। सभी एजेंसियों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाया। अभियान के दौरान सात लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन दुर्भाग्यवश दो लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी।

स्थानीय पूछताछ में यह पहलू भी सामने आया है कि इमारत रेलवे लाइन के काफी नजदीक स्थित थी। ऐसे में ट्रेनों के आवागमन से होने वाले कंपन को भवन गिरने का एक संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। प्रशासन के अनुसार, घटनास्थल पर चलाया गया बचाव एवं राहत अभियान पूरा कर लिया गया है। इस हादसे ने रेलवे भूमि पर पुराने और जर्जर भवनों की स्थिति, अतिक्रमण तथा उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग ऐसी इमारतों की पहचान और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद हटाईं गईं ग्रैप-3 की पाबंदियां

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा दी हैं। मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि, क्षेत्र में ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के तहत लागू सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे।

आयोग के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दैनिक एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 204 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता में सुधार के रुझान को देखते हुए आयोग की ग्रैप



उपसमिति ने मौजूदा हालात और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की समीक्षा की। उपसमिति ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमानों का भी जायजा लिया। अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में बने रहने की संभावना है। इसके बाद 6 नवंबर को लागू किए गए ग्रैप के तीसरे चरण को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया गया। हालांकि, आयोग के 30 अक्टूबर के आदेश के तहत 5 से 20 नवंबर तक लागू कुछ विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे। इसके तहत पूरे एनसीआर में छूट प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।

दस साल में मलेरिया से होने वाली मौत के मामलों में 80 प्रतिशत की कमी: राष्ट्रपति

आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली,एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत ने मलेरिया नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2015 से 2025 के बीच देश में मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में करीब 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या भी 155 से घटकर 33 रह गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से 2025 के दौरान देश के 160 जिलों में मलेरिया का एक भी स्थानीय मामला सामने नहीं आया। यह उपलब्धि वैज्ञानिकों, स्वास्थ्यकर्मियों, सरकार और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

राष्ट्रपति मंगलवार को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (एनआईएमआर) के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कर रही थीं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं



परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने संस्थान से जुड़े वर्तमान और पूर्व वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं तथा स्वास्थ्यकर्मियों को 50 वर्षों की वैज्ञानिक सेवा और मलेरिया नियंत्रण में योगदान के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि मलेरिया लंबे समय तक भारत की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में इस बीमारी का व्यापक प्रभाव देखने को मिला। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि गांवों में मलेरिया के कारण लोगों की आजीविका, शिक्षा और भविष्य प्रभावित होते देखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मरीजों को दवाओं का निर्धारित कोर्स पूरा करने के प्रति जागरूक करना जरूरी है, ताकि बीमारी का प्रभावी उपचार हो और दोबारा संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। राष्ट्रपति ने कहा कि मलेरिया के खिलाफ मिली सफलता को बनाए रखने के लिए लगातार सतर्कता बरतनी होगी। इसके लिए जांच, उपचार और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ मच्छरों पर नियंत्रण, नई दवाओं और टीकों के विकास तथा जनजागरूकता अभियान को गति देनी होगी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ हर उस गांव और समुदाय तक पहुंचना चाहिए, जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण और मच्छरों में कीटनाशकों के प्रति बढ़ते प्रतिरोध को मलेरिया नियंत्रण के सामने उभरती चुनौतियां बताया। राष्ट्रपति ने जलभराव रोकने, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने और पर्यावरण प्रबंधन को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 'आयुष्मान भारत' योजना में किया शामिल

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले से दिल्ली के पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का निर्णय इसी सोच का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस पहल से समुदाय के लोगों को विभिन्न बीमारियों के इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। सरकार का प्रयास है कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सम्मानजनक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के परिवारों को हर साल 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इसमें



अस्पताल में भर्ती होकर कराए जाने वाले विशेषज्ञ और गंभीर बीमारियों के इलाज शामिल होंगे। लाभार्थी देशभर के आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं के तहत 1,961 उपचार पैकेज और प्रक्रियाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य कवर में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाले 5 लाख रुपये के कवर और दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर शामिल है। इस तरह प्रत्येक पात्र परिवार को कुल 10 लाख रुपये का सालाना स्वास्थ्य कवर मिलेगा। सरकार ने इस योजना के तहत दिल्ली में लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संभावित लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया है।

यह अनुमान वर्ष 2011 की जनगणना में दर्ज 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या के आधार पर वर्ष 2026 के लिए लगाया गया है। लाभार्थियों की पहचान दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की प्रमाणित सूची के आधार पर की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र होना अनिवार्य होगा। इससे पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। इस प्रस्ताव के तहत राज्य बजट से प्रति वर्ष लगभग 1.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का प्रमुख उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को इलाज पर अपनी जेब से होने वाले भारी खर्च से राहत दिलाना है। गंभीर बीमारियों के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने पर कई बार परिवारों को बड़ी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा।

दिल्ली में ट्रैफिक जाम, पार्किंग व्यवस्था पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यातायात जाम और अव्यवस्थित पार्किंग को गंभीरता से लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के कई प्रमुख बाजारों और यातायात के व्यस्त केंद्रों पर लगने वाला जाम वायु गुणवत्ता को खराब करने में योगदान दे रहा है। इसे देखते हुए आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), एनडीएमसी समेत विभिन्न संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में आयोग ने सरोजिनी नगर मार्केट, सदर बाजार और लाला लाजपत राय मार्केट सहित दिल्ली के उन प्रमुख इलाकों में यातायात प्रबंधन दुरुस्त करने पर जोर दिया, जहां अक्सर भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यातायात के अत्यधिक दबाव वाले स्थानों पर वाहनों की आवाजाही सुचारु बनाई जाए, ताकि जाम के कारण वाहनों से होने वाले अतिरिक्त उत्सर्जन को कम किया जा सके। आयोग ने विशेष रूप से घनी आबादी और अधिक भीड़भाड़ वाले बाजारों में पार्किंग सुविधाएं बढ़ाने और उन्हें व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मल्टीलेवल पार्किंग (एमएलपी) का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है। आयोग ने सतही पार्किंग शुल्क को तर्कसंगत बनाने पर भी विचार करने का निर्देश दिया है, ताकि पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पेट्रोल पंपों पर जांच अभियान चलाने को कहा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' आदेश का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने वाले वाहनों को ईंधन देने पर रोक के नियम को लागू कराने के लिए पेट्रोल पंपों पर नियमित जांच की जाएगी। आयोग ने एनडीएमसी, दिल्ली छावनी बोर्ड और एमसीडी को निर्देश दिया है कि बाजारों और सड़कों की प्रतिदिन सुबह शुरुआती घंटों में उचित सफाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही बायोमास और कचरा जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने को कहा गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि खुले में कचरा और जैविक अपशिष्ट जलाने की घटनाएं किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आयोग ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को युद्धस्तर पर काम करने और अपने प्रयासों का असर जमीन पर दिखाने की हिदायत दी है। आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता जांचने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए जाएंगे, जो विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करें।

उत्तर रेलवे चलाएगा तीन जोड़ी विशेष ट्रेनें, दिल्ली से मालदा टाउन, छपरा, थावे और गोरखपुर के लिए सुविधा

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र से मालदा टाउन, छपरा, थावे और गोरखपुर के बीच तीन जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें शकूरबस्ती, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली जंक्शन से संचालित होंगी। इनमें एक जोड़ी आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी की होगी, जबकि दो जोड़ी पूरी तरह अनारक्षित रहेंगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने मंगलवार को बताया कि गाड़ी संख्या 03457 मालदा टाउन-शकूरबस्ती फेस्टिवल स्पेशल 18 नवंबर को सुबह 10 बजे मालदा टाउन से रवाना होकर अगले दिन शाम 5 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03458 शकूरबस्ती-मालदा टाउन स्पेशल 19 नवंबर को शाम 6:50 बजे शकूरबस्ती से रवाना होकर तीसरे दिन तड़के 1:45 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के डिब्बे होंगे। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में न्यू फरक्का, बरहरवा, साहिबगंज, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर, अभयपुर, किऊल, मोकामा, बख्तियारपुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना जंक्शन, दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, टूंडला और दिल्ली जंक्शन पर ठहरेगी।

गोपाष्टमी गौमाता की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने वालों को याद करने का अवसर भी : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि गोपाष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह गोमाता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले लोगों को याद करने का अवसर भी है। गुप्ता ने मंगलवार को मयूर विहार फेज-1 में गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गोमाता के प्रति श्रद्धा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक परंपराओं और सभ्यतागत विरासत के साथ हमारे गहरे संबंध को भी प्रतिबिंबित करती है।

सात नवंबर 1966 की घटनाओं का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष की गोपाष्टमी का विशेष ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह संसद के निकट गोहत्या पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर



हुए आंदोलन के छह दशक पूरे होने का अवसर है। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के उद्देश्य से संघर्ष करते हुए संत-महात्माओं को कारावास, कानूनी कार्यवाहियों और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, 'जब-जब समाज के समक्ष उसके गहरे मूल्यों और मान्यताओं को लेकर चुनौती उत्पन्न हुई है, तब-तब संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने असाधारण व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के माध्यम से समाज की सामूहिक चेतना को जागृत किया है। उल्लेखनीय है कि गोपाष्टमी यह पर्व उस पावन अवसर की स्मृति में मनाया जाता है जब भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में गायों की सेवा और देखभाल का दायित्व संभालना प्रारंभ किया था। यह बछड़ों की देखभाल से आगे बढ़कर गोपालक की जिम्मेदारी निभाने की उनकी यात्रा का प्रतीक है, जिसके लिए उन्हें गोप और गोविंद के रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के साथ गोमाता का यह पावन संबंध भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना में उनके शाश्वत महत्व को दर्शाता है।

महापौर प्रवेश वाही ने अमित शाह से की मुलाकात, निगम के विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर की चर्चा

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मंगलवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों, स्वच्छता अभियान और आगामी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। महापौर वाही ने बताया कि अमित शाह ने निगम के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कूड़ा निस्तारण और शहर में कूड़े के ढलावों को समाप्त करने की दिशा में चल रहे प्रयासों से भी गृह मंत्री को अवगत कराया। बैठक के दौरान कूड़े से बिजली उत्पादन को लेकर शुरू होने वाली चार नई परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। ये परियोजनाएं तेहखंड, ओखला, गाजीपुर और भलस्वा में स्थापित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से कूड़ा प्रबंधन को बेहतर बनाने के साथ-साथ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। महापौर ने बताया कि निगम आने वाले दिनों में प्रत्येक सप्ताह विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके अलावा निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 6.25 लाख विद्यार्थियों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लगभग 70 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। महापौर प्रवेश वाही ने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद दिल्ली नगर निगम के कार्यों में विशेष रुचि लेने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने आश्वस्त किया कि निगम के विकास, स्वच्छता और जनहित से जुड़े कार्यों को और अधिक गति देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया जाएगा।

स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने की समीक्षा बैठक, जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने मंगलवार को निगमायुक्त संजीव खिरवार, अतिरिक्त आयुक्तों तथा सभी जोन के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में निगम के विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। करुणामूलक आधार पर नियुक्ति एवं कर्मचारियों के नियमितीकरण, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, खतरनाक और जर्जर इमारतों के संबंध में कार्रवाई तथा उस्मानपुर एमसीडी स्टाफ क्वार्टर के पुनर्विकास से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल रहे।

बैठक के दौरान सत्या शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निगम में अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि पात्र आश्रितों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। उन्होंने ऐसे आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित मामलों का भी प्राथमिकता के साथ निपटारा करने के निर्देश दिए। इस प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी के लिए प्रत्येक माह में समीक्षा बैठक आयोजित की जाए, जिससे लंबित मामलों की स्थिति की नियमित समीक्षा हो सके और आवश्यक कार्रवाई समय पर सुनिश्चित की जा सके। वायु



प्रदूषण के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए स्थायी समिति अध्यक्ष ने सभी जोन के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों के प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखें। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जमा मलबे को समय पर हटाया जाए, ताकि धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने सभी जोन में डीप क्लीनिंग अभियान को और तेज करने तथा निर्माण गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और नियमानुसार चालान किए जाएं। बैठक में खतरनाक एवं जर्जर इमारतों की पहचान और उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी इमारतों का नियमित निरीक्षण किया जाए और जहां भी सुरक्षा संबंधी खतरा पाया जाए, वहां नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त उस्मानपुर एमसीडी स्टाफ क्वार्टर के पुनर्विकास से जुड़े मुद्दे पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की।

दिल्ली महिला आयोग में नियुक्ति गड़बड़ी मामले में 4 दिसंबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं किए जा सके। स्पेशल जज रुबी नीरज कुमार ने 4 दिसंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। मंगलवार को गवाह इंस्पेक्टर कैलाश चंद का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया जाना था, लेकिन वो न्यायालय का समन तामील होने के बावजूद पेश नहीं हुए। अभियोजन पक्ष ने बताया कि इंस्पेक्टर कैलाश चंद की तैनाती भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कानून व्यवस्था संभालने के लिए की गई है, इसलिए वे आज बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हो सके हैं। उसके बाद न्यायालय ने इंस्पेक्टर कैलाश चंद को 4 दिसंबर को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल समेत सभी आरोपित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये न्यायालय में पेश हुए। इसके पहले इस मामले में 4 नवंबर को शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक बरखा सिंह के बयान दर्ज किए गए। न्यायालय ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। न्यायालय ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं। न्यायालय ने चारों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा सिंह ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया।

दिल्ली महिला आयोग ने शिकायतों के पंजीकरण के लिए वॉट्सऐप नंबर किया जारी

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग ने आज महिलाओं की लिखित शिकायतों के पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक सुलभ एवं सुविधाजनक बनाने के लिए वॉट्सऐप नंबर 9217722609 जारी किया गया है। यह जानकारी मंगलवार को एक विज्ञप्ति के जरिए दी गई। इस सुविधा के माध्यम से महिलाओं को अपनी लिखित शिकायतें सीधे वॉट्सऐप के जरिए दिल्ली महिला आयोग तक पहुंचाने के लिए एक अतिरिक्त डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराया गया है। आयोग सभी महिलाओं से अपील करता है कि वे अपनी लिखित शिकायतों के पंजीकरण के लिए वॉट्सऐप नंबर 9217722609 का उपयोग कर सकती हैं।

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक



नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र के दौरान दिल्ली के विकास और जनोपयोगी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर एवं सार्थक चर्चा की जाएगी। सरकार जनहित सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले आज मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात करके 18 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र सहित राजधानी के विकास, जनहित और भविष्य की प्राथमिकताओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप दिल्ली को आधुनिक सुविधाओं, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और बेहतर जीवन स्तर वाली विश्वस्तरीय राजधानी बनाना हमारा लक्ष्य है। इसी दिशा में सभी के सहयोग एवं समन्वय से दिल्ली के विकास को नई गति देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

एमसीडी ने सभी 12 जोनों के छठ घाटों पर चलाया स्वच्छता अभियान

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने छठ पूजा के बाद दिल्ली के सभी 12 जोनों के अंतर्गत आने वाले छठ घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इसका उद्देश्य पर्व के दौरान एवं उसके समापन के बाद घाटों और उनके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता, साफ-सफाई एवं स्वास्थ्यकर वातावरण सुनिश्चित करना था। इसके लिए विभिन्न घाटों पर विशेष स्वच्छता दलों के साथ अतिरिक्त कर्मचारियों एवं मशीनरी की तैनाती की गई, ताकि नियमित सफाई, कचरा संग्रहण एवं अन्य स्वच्छता संबंधी कार्य प्रभावी ढंग से किए जा सकें।

निगमायुक्त संजीव खिरवार ने सभी जोनल उपायुक्तों (डीसी) को निर्देश दिए कि सांध्य और उषा अर्घ्य के बाद घाटों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों की तत्काल एवं व्यापक सफाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, नगर निगम के ठोस कचरे तथा निर्धारित खंडित मूर्ति संग्रहण पात्रों में एकत्रित सामग्री का उचित संग्रहण एवं निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सभी जोनल उपायुक्त एवं संबंधित अधिकारी स्वच्छता व्यवस्था की निगरानी के लिए सक्रिय रूप से क्षेत्र में मौजूद रहें। पूर्वी जोन में 'स्वच्छ



एवं हरित छठ पूजा' पहल के अंतर्गत पूजा सामग्री एवं अन्य कचरे के पृथक संग्रहण के लिए ट्विन-बिन ई-रिक्शा रणनीतिक रूप से तैनात किए गए। पर्व से पहले, पर्व के दौरान एवं उसके बाद स्वच्छता बनाए रखने के लिए तीन पालियों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई। इसके अतिरिक्त, घाटों के आसपास धूल प्रदूषण को कम करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर एवं पानी के टैंकर भी लगाए गए।

पश्चिमी जोन में सभी छठ घाटों पर विशेष स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई तथा अधिकतम संख्या में कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया गया। घाटों से ठोस कचरा हटाया गया। इसके साथ ही छठ पूजा आयोजकों के समन्वय से पर्व के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचों को भी हटाया गया। दक्षिणी जोन में 23 वार्डों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें संबंधित सभी वार्डों के सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। कचरे के समयबद्ध संग्रहण एवं परिवहन तथा घाटों की प्रभावी सफाई सुनिश्चित करने के लिए लगभग 150 अतिरिक्त कर्मचारियों और 23 टिप्परों को तैनात किया गया। सभी जोनों में पर्व के अवसर पर बनाए गए कृत्रिम छठ घाटों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया। पूजा संपन्न होने के बाद इन अस्थायी घाटों में भरे पानी की निकासी की गई, ताकि जलभराव न हो और मच्छरों के प्रजनन की संभावना को कम किया जा सके। अन्य जोनों में भी इसी प्रकार के विशेष प्रबंध किए गए।

एक नजर

पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर युवक लापता, नहर में तलाश जारी

फरीदाबाद। फरीदाबाद के गांव मवई निवासी 24 वर्षीय युवक अरमान खान शादी के करीब साढ़े नौ महीने बाद मंगलवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। लापता होने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाकर अपने पिता को भेजा, जिसमें उसने पत्नी पर शक करने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। वीडियो में उसने आगरा नहर में कूदने की बात भी कही। इसके बाद उसकी बाइक और मोबाइल फोन कटला पुल के पास नहर किनारे मिले। परिजनों के अनुसार, अरमान जोमैटो में काम करने के साथ बीफार्मा की पढ़ाई कर रहा था। मंगलवार सुबह उसने पिता अख्तर खान को वीडियो भेजा। परिजनों ने उससे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन नहीं उठा। सुबह करीब छह बजे नहर किनारे उसकी बाइक और मोबाइल मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने नहर में तलाश शुरू की। अरमान के पिता ने आरोप लगाया कि पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते पहले भी तीन बार पंचायत हो चुकी थी। करीब एक महीने से अरमान अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। उसकी पत्नी आठ महीने की गर्भवती बताई जा रही है। खेड़ी थाना प्रभारी राकेश के अनुसार, दोनों के बीच पहले भी पारिवारिक विवाद हुआ था। पुलिस ने उस समय समझाकर मामला शांत करा दिया था। उन्होंने बताया कि युवक को नहर में कूदते किसी ने नहीं देखा है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है। युवक के मिलने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

एक दिसंबर से जिले के सभी स्कूलों में चलेगा सुरक्षित बचपन अभियान : नेहा गुप्ता

नूंह। बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने और उन्हें अपने अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नूंह जिले में एक दिसंबर से सुरक्षित बचपन अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत 30 नवंबर 2027 तक जिले के सभी स्कूलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), नूंह के एडीआर सेंटर में जिले के सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के दो-दो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा गुप्ता ने की। उन्होंने शिक्षकों को सुरक्षित बचपन अभियान के उद्देश्यों, इसकी रूपरेखा और प्रस्तावित गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाव के प्रति जागरूक करना है। नेहा गुप्ता ने कहा कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य और उनके सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्कूल ऐसा माध्यम हैं, जहां बच्चों तक सही जानकारी पहुंचाकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों को सुरक्षा से जुड़े जरूरी पहलुओं की जानकारी दे, ताकि बच्चे किसी भी प्रकार के शोषण या गलत व्यवहार के प्रति सजग रह सकें।

चार दिन तक रही जलापूर्ति बाधित, ठेकेदार पर एक लाख जुर्माना

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने पेयजल आपूर्ति में लापरवाही बरतने पर संबंधित ठेकेदार पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। वार्ड-10 की हरि नगर कालोनी में लगातार चार दिनों तक जलापूर्ति बाधित रही। इसी के चलते निगम ने यह सख्त फैसला लिया। मंगलवार को नगर निगम आयुक्त की ओर से यह जानकारी दी गई। नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार निगम क्षेत्र के हरि नगर खांडसा रोड के पास स्थित वार्ड-10 में चार दिनों तक लगातार पानी की आपूर्ति बाधित रही। इस कारण क्षेत्र के निवासियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस मामले को नगर निगम आयुक्त ने गंभीरता से लिया। मैसर्स नरेंद्र सिंह कॉन्ट्रेक्टर को नगर निगम के वार्ड नंबर 9, 10, 16 और 17 में जलापूर्ति नेटवर्क एवं बूस्टिंग स्टेशनों के संचालन और रखरखाव का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य के लिए एजेंसी को 24 जुलाई 2026 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। इसके बावजूद वार्ड-10 के हरि नगर क्षेत्र में लगातार चार दिनों तक जलापूर्ति बाधित रहना एजेंसी के कार्य प्रदर्शन और आवश्यक जनशक्ति की तैनाती को लेकर गंभीर चिंता का विषय पाया गया। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जलापूर्ति बाधित रहने के दौरान प्रभावित क्षेत्र में पानी के टैंकरों की व्यवस्था भी नहीं की गई। नगर निगम ने जलापूर्ति व्यवस्था के उचित रखरखाव में हुई चूक को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एजेंसी पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित वार्ड में जलापूर्ति व्यवस्था का उचित संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। निगमायुक्त डॉ. पंकज ने कहा कि जुर्माने की राशि संबंधित एजेंसी के रनिंग बिल से वसूल की जाएगी। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नागरिकों को पेयजल जैसी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित एजेंसियों को निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य करना होगा तथा जलापूर्ति बाधित होने की स्थिति में नागरिकों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रति भी जवाबदेह रहना होगा।

प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : प्रदीप सिंह

गुरुग्राम,एजेंसी। मानेसर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए नगर निगम मानेसर ने सख्त रूख अपनाया है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निगम आयुक्त प्रदीप सिंह ने मंगलवार को निगम अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

आयुक्त प्रदीप सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को युद्धस्तर पर काम करते हुए ग्रेप की पाबंदी में निर्माण गतिविधियों, खुले में कूड़ा डालने और कूड़े में आग लगाने जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगानी होगी। आयुक्त प्रदीप सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगम क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस की निती अपनाई जाए। खुले में कचरा डालने, कूड़ा जलाने और निर्माण गतिविधियों के माध्यम से धूल फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था और सैनिटेशन विंग की



जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण केवल कागजी आदेशों से संभव नहीं है, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को धरातल पर उतरकर नियमित निगरानी करनी होगी। वे स्वयं निगम क्षेत्र में औचक निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाए। बैठक में आयुक्त ने विशेष तौर पर सफाई कार्यप्रणाली पर जोर दिया। उन्होंने सहायक सफाई निरीक्षकों को आदेश किए कि वे अपने-अपने वार्डों और गांवों में टीम के साथ प्रतिदिन कम से कम तीन बार गश्त करें। इस दौरान खुले में पड़े कूड़े, कचरे में आग लगाने की घटनाओं और निर्माण मलबे और सडक़ों के किनारे जमा धूल और मिट्टी की स्थिति पर विशेष नजर रखें। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी भी क्षेत्र में सफाई या प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कमी मिलने पर संबंधित सहायक सफाई निरीक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे। आयुक्त ने कहा कि निगम क्षेत्र में मलबा, सॉलिड वेस्ट और सडक़ों एवं गलियों के किनारे जमा धूल और रेत की डीप क्लीनिंग करवाई जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक कचरे को खुले स्थानों, खाली प्लॉटों और सडक़ों के किनारे डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि कोई वाहन औद्योगिक कचरा खुले में डालता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका अधिकतम चालान किया जाए। साथ ही संबंधित वाहन को जब्त करके आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को लिखित में सूचित किया जाए। बैठक में संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार, दर्शन यादव, एक्सईएन मंदीप धनखड़, सुशील ठाकरान, वासु बग्गन, निजेश, एसडीओ अनिल मलिक, विकास शर्मा, रविंद्र दहिया, शशिकांत, अमन राठी, संजय बंसल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

1.75 करोड़ की लागत से बनी सड़क दो महीने में ही गुणवत्ता जांच में फेल

फरीदाबाद। डबुआ कॉलोनी में सरकारी धन से बनाई गई सडक़ की गुणवत्ता की पोल महज दो महीने में खुल गई। करीब 1.75 करोड़ रुपये की लागत से 17 नंबर चुंगी से नवादा गांव तक बनाई गई एक किलोमीटर लंबी आरएमसी सडक़ का सैंपल जांच में तय मानकों पर खरा नहीं उतरा। रिपोर्ट सामने आने के बाद नगर निगम ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही शेष भुगतान पर रोक लगा दी है। सडक़ निर्माण के दौरान ही स्थानीय लोगों ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए शिकायतें की थीं। इसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट अजय ने भी सडक़ निर्माण और गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों से जानकारी मांगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने सडक़ के सैंपल जांच के लिए भेजे, जिनकी रिपोर्ट में गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। स्थानीय लोगों की शिकायतों के अनुसार, सडक़ पर पानी की निकासी के उचित इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कई जगह सडक़ ऊबड़-खाबड़ है और इसे समतल बनाने में भी लापरवाही बरती गई है। इससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या पैदा होने की आशंका है। गौरतलब है कि शहर में खराब सडक़ों का मुद्दा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में भी उठ चुका है। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सडक़ निर्माण में गुणवत्ता की कमी पर अधिकारियों और ठेकेदारों के प्रति नाराजगी जताई थी। इसके बाद नगर निगम ने तीन सडक़ों को तुड़वाकर दोबारा बनवाया था। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

गुरुग्रामः 50 लाख का पैकेज छोड़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अक्षिता बनीं साध्वी

गुरुग्राम,एजेंसी। यहां मल्टीनेशनल कंपनी फॉक्सवैगन में 50 लाख रुपये सालाना पैकेज पर नौकरी करने वाली 37 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अक्षिता जैन ने अपनी मां शिरोमणी (61) के साथ दीक्षा दी। अब दोनों मां-बेटी जैन साध्वी बन गई हैं। अक्षिता अब तक फिएट कंपनी, मर्सिडीज बेंज और फॉक्सवैगन जैसी कंपनियों में नौकरी कर चुकी हैं, जबकि उनकी मां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 37 साल नौकरी करने के बाद चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुई हैं। दोनों मां-बेटी पंजाबी हिंदू परिवार से हैं।

दीक्षा से पहले मंगलवार को जोधपुर में उनका वरघोड़ा निकाला गया। इसमें जैन समाज के साधु-साध्वियों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अक्षिता की मां शिरोमणी बजाज का जन्म 18 अक्टूबर 1965 को दिल्ली के मोती नगर में हुआ था। उन्होंने बीए और लाइब्रेरी साइंस में बीलिब की डिग्री हासिल की। शिरोमणी ने छह जनवरी 1988 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में नौकरी शुरू की थी। 31 अक्टूबर 2025 को चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुईं। इस तरह उन्होंने आईओसीएल में 37 साल से अधिक समय तक सेवाएं दीं। शिरोमणी के पति सुनील बजाज का निधन हो चुका है। उनकी दो बेटियां अक्षिता और आशिमा हैं। आशिमा की शादी हो चुकी है। उनके परिवार में दामाद सिद्धार्थ बजाज और चार साल की नातिन इनायत भी हैं। शिरोमणी का परिवार मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है। वह फिलहाल गुरुग्राम में रह रहा है। अक्षिता जैन (37) गुरुग्राम की रहने वाली हैं। उन्होंने 2013 से 2015 तक गुरुग्राम की नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री की। इसके बाद आईआईएम बेंगलुरु से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। उन्होंने 2015 से 2017 तक फिएट ऑटो में काम किया। इसके बाद 2018 से 2025 तक मर्सिडीज बेंज में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर सेवाएं दीं। वर्ष 2025 से 2026 तक वह फॉक्सवैगन में ग्लोबल ऑपरेशन मैनेजर रहीं। इस दौरान उन्होंने दुनिया के पांच अलग-अलग लोकेशन का संचालन संभाला। वर्तमान में उनका सालाना पैकेज 50 लाख रुपए था। अक्षिता ने आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख करने की वजह बताते हुए कहा कि वह उस पीढ़ी से हैं, जिसने फोन और इंटरनेट को आते हुए देखा है। जब कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर काम शुरू हुआ तो उन्हें महसूस हुआ कि एआई और डेटा सेंटर से जुड़ी गतिविधियों में भी सूक्ष्म जीवों की विराधना हो सकती है।

महिला पेशेवर गोल्फ टूर : रिधिमा ने बनाई बढ़त, रिया जादोन एक शॉट पीछे

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। हीरो महिला पेशेवर गोल्फ टूर-2026 के 15वें और अंतिम चरण के पहले दिन रिधिमा दिलावरी ने शानदार शुरुआत करते हुए बढ़त बना ली। जयपी विशटाउन गोल्फ कोर्स में खेले जा रहे इस मुकाबले में हीरो ऑर्डर ऑफ मेरिट की शीर्ष खिलाड़ी रिधिमा ने दो अंडर 69 का स्कोर बनाया। वह इस सत्र में चार खिताब जीत चुकी हैं।

रिया जादोन ने एक अंडर 70 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। एमेच्योर गोल्फर ऐडा थिम्मैया ने अनुभवी पेशेवर खिलाड़ियों वाणी कपूर और त्वेसा मलिक के साथ पार 71 का स्कोर करते हुए संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। पहले दिन खिलाड़ियों को जयपी विशटाउन गोल्फ कोर्स पर काफी चुनौती मिली। केवल दो खिलाड़ी ही बेहतर स्कोर कर सकीं, जबकि तीन खिलाड़ियों ने पार स्कोर बनाया। इससे इस कोर्स की कठिन परिस्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। रिधिमा ने चार बर्डी और दो बोगी के साथ 69 का कार्ड खेला। इस साल उन्होंने कलहार ब्लूज एंड ग्रीन्स, पूना क्लब, जयपी विशटाउन और प्रेस्टीज गोल्फशायर में खिताब जीते हैं। इसके अलावा वह दो बार उपविजेता भी रही हैं और हीरो ऑर्डर ऑफ मेरिट में शीर्ष पर कायम हैं। रिधिमा ने इस सत्र का अपना पिछला खिताब 12वें चरण में प्रेस्टीज गोल्फशायर में जीता था। पिछले सप्ताह रामबाग



गोल्फ क्लब में हुए 14वें चरण में वह तीसरे स्थान पर रही थीं। उस मुकाबले में जैस्मिन शेखर विजेता और वाणी कपूर उपविजेता बनी थीं। जैस्मिन इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रही हैं। वह थाईलैंड में क्यू-स्कूल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छह भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं।

रिया जादोन ने भी पहले दिन अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने फ्रंट नाइन में दो बर्डी लगाईं, जबकि बैक नाइन में एक बोगी की। इस तरह उन्होंने एक अंडर 70 का स्कोर बनाकर रिधिमा के साथ खिताबी मुकाबले को रोचक बना दिया। बेंगलुरु की एमेच्योर गोल्फर ऐडा थिम्मैया ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अनुभवी पेशेवर खिलाड़ियों के बीच खेलते हुए उन्होंने तीन बर्डी और तीन बोगी के साथ पार 71 का स्कोर बनाया। वह वाणी कपूर और त्वेसा मलिक के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर हैं। बैक नाइन में दो बार ऐसा हुआ, जब उन्होंने बर्डी लगाई, लेकिन अगले ही होल में अपना स्ट्रोक गंवा दिया। इस साल दो खिताब जीत चुकीं वाणी कपूर का प्रदर्शन पहले और दूसरे नौ होल में अलग-अलग रहा। उन्होंने शुरुआत डबल बोगी से की और फ्रंट नाइन में एक बर्डी के मुकाबले तीन बोगी लगाईं। इस कारण वह तीन ओवर पर पहुंच गईं। हालांकि, बैक नाइन में उन्होंने शानदार वापसी की और तीन बर्डी के साथ तीन अंडर 32 का स्कोर बनाया। इस तरह उनका कुल स्कोर पार 71 रहा। वाणी ने इस सत्र में नौवें और 13वें चरण के खिताब जीते हैं। इसके अलावा वह तीन बार उपविजेता रही हैं। हीरो महिला इंडियन ओपन में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। त्वेसा मलिक ने भी पार 71 का स्कोर बनाया, लेकिन उनका प्रदर्शन वाणी से उलट रहा। उन्होंने फ्रंट नाइन में तीन अंडर 33 का स्कोर किया। सातवें होल से लगातार तीन बर्डी लगाकर उन्होंने अच्छी शुरुआत की। हालांकि, बैक नाइन में कोई बर्डी नहीं लगा सकीं और तीन स्ट्रोक गंवा दिए। हीरो महिला इंडियन ओपन में भी त्वेसा ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक अंडर 287 (71-73-71-72) के कुल स्कोर के साथ सातवां स्थान हासिल किया था।

नूंहः अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, 25 वाहन जब्त कर 11.72 लाख रुपये की पेनल्टी वसूली

नूंह,एजेंसी। नूंह जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन में संलिप्त 25 वाहनों को जब्त किया गया है। इन मामलों में कुल 11 लाख 72 हजार 140 रुपये की पेनल्टी वसूल की गई है। अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन संभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलटीएफसी) की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में जिले में अवैध खनन की रोकथाम, खनिजों के अवैध परिवहन और संबंधित विभागों की कार्रवाई की समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जब्त किए गए 25 वाहनों में से 16 वाहन बिना ई-रवाना के खनिजों का परिवहन करते हुए पकड़े गए हैं, जबकि 9 वाहन अंतरराज्यीय परिवहन पास



(आईएसटीपी) से संबंधित नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इन वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित मामलों में 11,72,140 रुपये की पेनल्टी वसूल की गई है। ज्योति ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी निगरानी रखें। विशेष रूप से संवेदनशील एवं अवैध खनन संभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खनन विभाग, वन विभाग तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नूंह के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आपसी तालमेल के साथ अवैध खनन संभावित क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान मौके की स्थिति का जायजा लेकर नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नियमित निरीक्षण से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन और खनिजों का नियमों के विरुद्ध परिवहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचने के साथ पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मोबाइल की जगह जांगी एप से बात और फर्जी नामों का इस्तेमाल

गाजियाबाद। असली पहचान छिपाने के लिए छद्म नाम, बातचीत के लिए जांगी एप और गांजे की खेप पहुंचाने के लिए अलग-अलग रास्ते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर में गांजा तस्करी का नेटवर्क चलाने वाले दो आरोपितों ने पुलिस से बचने के लिए पूरा तरीका अपना रखा था। दोनों एक-दूसरे को असली नाम के बजाय गलत नामों से बुलाते थे। ओडिशा और विशाखापट्टनम के तस्करों से गांजे की डील भी इसी नेटवर्क के जरिये होती थी। पुलिस की अपराध शाखा और मुरादनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों पकड़े गए। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 80 लाख रुपये कीमत का 164 किलोग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल होने वाला कंटेनर बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपितों की पहचान निवाड़ी रोड स्थित केशव कुंज कॉलोनी निवासी प्रवीण त्यागी और मेरठ के जटौली गांव निवासी अरुण शर्मा के रूप में हुई है। दोनों के बीच पुरानी जान-पहचान थी। वर्ष 2017 से दोनों अवैध शराब की तस्करी में साथ काम कर रहे थे।

फर्जी बैंक खातों और ऑनलाइन जुए के अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़

नूंह। नूंह जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुन्हाना सदर थाना पुलिस और साइबर क्राइम नूंह की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन जुआ और साइबर ठगी के अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नीमखेड़ा गांव में जमालगढ़ मोड़ के पास दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 45 मोबाइल फोन, 139 एटीएम कार्ड, 20 बैंक पासबुक, 13 चेकबुक, 35 सिम कार्ड और चार लैपटॉप सहित बड़ी संख्या में क्यूआर कोड, आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुन्हाना सदर थाना क्षेत्र में उपनिरीक्षक नंद किशोर के नेतृत्व में पुलिस टीम साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए जमालगढ़ मोड़ पर मौजूद थी। इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि कुछ युवक नीमखेड़ा क्षेत्र में फर्जी बैंक खाते, चेकबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऑनलाइन जुए के माध्यम से ठगी का नेटवर्क चला रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने साइबर क्राइम नूंह की टीम के साथ मौके पर दबिश दी। वहां चार युवक मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन जुआ संचालित करते मिले। पुलिस ने मौके पर ही चारों को काबू कर लिया। उनकी पहचान साजिद निवासी अखनाका, थाना फिरोजपुर झिरका (नूंह), अफरोज निवासी कीडोरे, थाना पहाड़ी, जिला डीग (राजस्थान), फरहान निवासी नजीबपुर खेतासर, थाना टिकैत नगर, जिला बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) और जितेश कुमार बैरवा निवासी रानीवास, पोस्ट लाडोती का बास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा (राजस्थान) के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर मौके से अलग-अलग कंपनियों के 45 मोबाइल फोन, विभिन्न बैंकों के 139 एटीएम कार्ड, 20 बैंक खातों की पासबुक, 13 चेकबुक, 35 सिम कार्ड और चार लैपटॉप बरामद हुए।

गुरुग्रामः विकास व प्रदूषण नियंत्रण के लिए 61.10 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी

गुरुग्राम। निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम गुरुग्राम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मेयर राजरानी मल्होत्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में वित्त एवं संविदा समिति (एफएंडसीसी) की 11वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगमायुक्त डॉ. पंकज, अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका व चीफ इंजीनियर विजय ढाका, निगम सचिव डॉ. सिद्धार्थ खंडेलवाल सहित अधीक्षक अभियंता और कार्यकारी अभियंता उपस्थित रहे।

बैठक में विभिन्न विकास एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े 14 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। समिति ने कुल 61 करोड़ 10 लाख 53 हजार रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। स्वीकृत प्रस्तावों में कचरा प्रबंधन, सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग, सडक़ सफाई एवं धूल नियंत्रण, एंटी-स्मॉग गन, स्ट्रीट लाइटों के संचालन एवं रखरखाव तथा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। समिति ने हीरो होंडा चौक के पास एनएच 48 पर सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट विकसित करने के लिए 3 करोड़ 53 लाख 20 हजार रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, जोन-5 में बेरी वाला बाग के पास डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों के लिए पार्किंग एवं चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए तीन करोड़ 93 लाख 53 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं से कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रणाली के संचालन को अधिक व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी। निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) वेस्ट के उचित प्रबंधन की दिशा में समिति ने दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी। बायोडायवर्सिटी पार्क में मोबाइल सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए 6 करोड़ 64 लाख 20 हजार रुपये तथा वजीराबाद में सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए 6 करोड़ 64 लाख 20 हजार रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मकान में लगी आग, बच्चों ने भागकर बचाई जान

गुरुग्राम,एजेंसी। यहां एक मकान में भीषण आग लगने से इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही पलों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में घर में रखा लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। गनीमत रही कि घटना के समय घर में मौजूद दोनों बच्चों ने समय रहते बाहर भागकर अपनी जान बचा ली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि आग से गैस सिलेंडर में भी आग लग गई।

पीड़ित मकान मालिक दया शंकर ने बताया कि वह एयरटेल कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि उनकी पत्नी भी एक अन्य कंपनी में नौकरी करती हैं। रोजाना की तरह सुबह करीब नौ बजे दोनों पति-पत्नी अपनी-अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकल गए थे। धूमसपुर क्षेत्र स्थित उनके मकान में उनके दो मासूम बच्चे अकेले थे, जो मुख्य गेट के पास खेल रहे थे। इसी दौरान घर के अंदर अचानक धुआं और आग की लपटें निकलती दिखाई दी। देखते ही देखते चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया। घर के अंदर से धुआं और आग की लपटें निकलती देख गेट के पास खेल रहे दोनों बच्चे सहम गए, लेकिन उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत घर से बाहर की



ओर दौड़ लगा दी और सुरक्षित बाहर निकल आए। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के पड़ोसी मौके पर जमा हो गए। आग की विकरालता को देखते हुए पूरी कॉलोनी में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। स्थानीय निवासियों ने तुरंत इस घटना की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाडयिां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। दमकल कर्मियों की तत्परता के कारण आग आसपास के सटे हुए अन्य मकानों तक नहीं फैल सकी, अन्यथा कॉलोनी में और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। आग बुझने के बाद जब घर का मंजर देखा गया तो अंदर सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मकान मालिक दया शंकर के अनुसार इस आगजनी में घर का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कपड़े, नकदी और अन्य जरूरी दस्तावेज पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, जिससे उन्हें लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

सपा-कांग्रेस गठबंधनः सीटों के पेच में उलझती सियासी राह

अशोक भाटिया



उत्तर प्रदेश की सियासी धरती हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा तय करती रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होने के साथ ही विपक्षी खेमे, विशेषकर 'इंडिया' गठबंधन के दो प्रमुख स्तंभों—समाजवादी पार्टी और कांग्रेस—के बीच सीटों के तालमेल को लेकर हलचल अपने चरम पर है। नई दिल्ली में 17 नवंबर 2026 को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीट बंटवारे पर होने वाली बहुप्रतीक्षित औपचारिक बैठक का ऐन वक्त पर टल जाना, सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों और चर्चाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि, इस स्थगन को केवल टकराव के रूप में देखने के बजाय गठबंधन की आंतरिक जटिलताओं, महत्वाकांक्षाओं के टकराव और चुनावी यथार्थ के बीच संतुलन साधने की एक कठिन कवायद के रूप में समझा जाना चाहिए। बैठक टलने के पीछे भले ही समन्वय समितियों के गठन और प्रारंभिक तैयारी का हवाला दिया गया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या और दावेदारी को लेकर अभी तक कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं बन पाया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कांग्रेस की वह प्रारंभिक सूची है, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव ने समाजवादी पार्टी के खेमे में स्वाभाविक रूप से असहजता पैदा कर दी है। सपा नेतृत्व, जो राज्य में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते खुद को गठबंधन के 'बड़े भाई' की भूमिका में देखता है, इतनी बड़ी संख्या में सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों और विभिन्न समाचार माध्यमों की खबरों के अनुसार, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 50 से 80 सीटों के दायरे में ही सीमित रखना चाहती है। सीटों की मांग और पेशकश के बीच का यह विशाल अंतर ही वह मुख्य पेच है, जिसके चलते 17 नवंबर की औपचारिक बैठक को तीन-चार दिनों के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत में यह सहमति बनी कि शीर्ष स्तर पर अंतिम मुहर लगने से पहले दोनों दल अपनी-अपनी समन्वय समितियों के माध्यम से जमीनी हकीकत और दावेदारी का आकलन करें। कांग्रेस ने इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और इमरान मसूद जैसे वरिष्ठ नेताओं की पांच सदस्यीय समिति का गठन कर अपनी गंभीरता दर्शाई है।

गठबंधन की इस खींचतान को समझने के लिए दोनों दलों के तर्कों और उनके पीछे के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालना आवश्यक है। कांग्रेस का उत्साह मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों से उपजा है, जहां सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं, जिससे विपक्षी गठबंधन को एक नई संजीवनी प्राप्त हुई थी। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में उसका जनाधार बढ़ा है और संगठन में नई जान फूंकी गई है। इसी आधार पर कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 67, अवध क्षेत्र की 51 और बुंदेलखंड की 9 सीटों सहित कुल 181 सीटों की सूची तैयार की है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का यह भी तर्क है कि यदि 2024 के लोकसभा परिणामों के अनुपात को आधार बनाया जाए, तो भी उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी के पास 2022 के विधानसभा चुनावों के ठोस आंकड़े हैं, जो कांग्रेस के दावों पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर लड़ते हुए महज दो सीटों पर जीत हासिल की थी, उसका वोट प्रतिशत चार फीसदी से भी नीचे (3.84 प्रतिशत) सिमट गया था और उसके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसके अलावा, हाल के वर्षों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने भी सपा को यह अहसास कराया है कि जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती और कैडर वोट का हस्तांतरण ही जीत की असली गारंटी है। अखिलेश यादव ने दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कसौटी का उल्लेख किया है—जिताऊ क्षमता)। उनका स्पष्ट कहना है कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराना है, और इसलिए जिस सीट पर जिस दल का उम्मीदवार जीतने की सबसे मजबूत स्थिति में होगा, वही वहां से चुनाव लड़ेगा।

राजनीति के व्यावहारिक धरातल पर सपा प्रमुख का यह तर्क अत्यंत वजनदार प्रतीत होता है। गठबंधन की राजनीति में अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई सहयोगी दल अपनी वास्तविक संगठनात्मक क्षमता से अधिक सीटों की जिद पकड़ लेता है और कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारता है, तो उसका सीधा लाभ विरोधी खेमे को मिलता है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का कड़वा अनुभव दोनों दलों के सामने एक जीवंत उदाहरण है। उस समय सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें दी गई थीं, लेकिन वह केवल सात सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी, जिसका खामियाजा पूरे गठबंधन को सत्ता से दूर रहकर भुगतना पड़ा था। सपा नेतृत्व कतई नहीं चाहेगा कि 2027 में 2017 की उस ऐतिहासिक भूल को दोहराया जाए। दूसरी ओर, कांग्रेस की अपनी मजबूरियां और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते यदि वह उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में केवल 50 या 60 सीटों पर सिमट जाती है, तो इससे न केवल राज्य के शेष हिस्सों में उसका संगठन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी उसके मनोबल और सौदेबाजी की ताकत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व उन सीटों पर भी दावा ठोक रहा है जहां पिछली बार सपा के विधायक जीते थे या सपा दूसरे स्थान पर रही थी, जिससे स्थानीय स्तर पर सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपना स्वाभाविक है। इस सियासी रस्साकशी के बीच यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का चुनावी मैदान केवल दो ध्रुवों तक सीमित नहीं है। एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने मजबूत बूथ प्रबंधन, सामाजिक इंजीनियरिंग और डबल इंजन सरकार की योजनाओं के दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं दूसरी तरफ, बहुजन समाज पार्टी और अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ऐसे बहुकोणीय या त्रिकोणीय मुकाबले में विपक्षी वोटों का जरा सा भी बिखराव सपा और कांग्रेस दोनों के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों ने सार्वजनिक रूप से यह दोहराया है कि 'इंडिया' गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करेगा। लेकिन शीर्ष नेताओं की यह सद्भावना तभी फलीभूत हो सकती है जब वह जमीनी कार्यकर्ताओं के स्तर तक पहुंचे। यदि सीटों के बंटवारे की घोषणा से पहले ही सूची लीक होने और एक-दूसरे की सीटों पर दावेदारी जताने का सिलसिला यूं ही चलता रहा, तो इससे मतदाताओं के बीच भ्रम और अविश्वास का संदेश जाएगा। दरअसल अब 17 नवंबर की बैठक का टलना कोई पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अल्पविराम है। राजनीति को संभावनाओं और समझौतों की कला कहा जाता है। आने वाले दिनों में जब दोनों दलों की समन्वय समितियां आमने-सामने बैठेंगी, तो उन्हें आंकड़ों की बाजीगरी और अहं के टकराव से ऊपर उठकर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना होगा। कांग्रेस को यह स्वीकार करना होगा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की धुरी समाजवादी पार्टी ही है और उसकी सांगठनिक ताकत के बिना भाजपा को चुनौती देना असंभव है। वहीं, समाजवादी पार्टी को भी बड़े भाई का उदार हृदय दिखाते हुए कांग्रेस को इतनी सम्मानजनक हिस्सेदारी अवश्य देनी होगी, जिससे कांग्रेस का पारंपरिक और अल्पसंख्यक मतदाता पूरे उत्साह के साथ गठबंधन के पक्ष में लामबंद हो सके। सीटों की इस बिसात पर यदि दोनों दल अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर केवल 'जीत' के साझा लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, तो निश्चित रूप से बात बन सकती है। अन्यथा, तालमेल की यह देरी और आपसी अविश्वास 2027 की चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही विपक्ष की धार को कुंद कर सकता है।

आज पेरिस समझौते को दस साल पूरे हो चुके हैं और ओजोन परत के मामलें में तो दुनिया के देशों ने एक तरह से सफलता प्राप्त कर ली है। इस समय तुर्किया के अंताल्या में दुनिया के देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं तो दूसरी और यह दूसरा मौका है जब अमेरिका ने इस सम्मेलन से किनारा किया है। यह महज संयोग ही नहीं है अपितु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हठधर्मिता ही मानी जानी चाहिए की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में चीन के साथ प्रमुख देश होने के बावजूद अमेरिका ने पेरिस समझौते से किनारा कर लिया है। ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल 2020 में भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर अनावश्यक बोझ बताते हुए किनारा किया और 2021 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद 2021 में शामिल होने की घोषणा की पर ट्रम्प ने दूसरे कार्यकाल में 2026 में एक बार फिर किनारा कर लिया है। हांलाकि यह अमेरिका का गैर जिम्मेदारान कदम है और दुनिया के देषों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सारी दुनिया प्रभावित हो रही है। अकेले सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की ही बात करें तो सालाना 90-92 लाख लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु की गुणवत्ता 2.5 पीएम के स्तर पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 तक को बेहतरीन माना गया है तो 51 से 100 तक भी संतोषजनक की श्रेणी में माना जा सकता है।

साफ हवा मिले तो सालाना बचे 90 लाख से भी अधिक जिंदगियां

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा



बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण अवष्य लगती है पर यदि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हालिया अध्ययन की ही माने तो केवल शुद्ध हवा मिलने लगे तो साल भर में देश-दुनिया में 90 लाख से अधिक जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण से अत्यधिक चिंताग्रस्त है। इसका कारण भी है और वह यह कि आज प्रकृति की विकृति से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे है। बेमौसम बरसात, आंधी-तूफान, जंगलों में दावानल, समुद्र में आए दिन तूफान, सुनामी और भू स्खलन से लेकर भूकंप की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है। तापमान में बढ़ोतरी, ग्लेसियरों के पिघलने की गति में तेजी आई है तो समुद्र के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने लगी है। सर्दी तो दूर आए दिन वायु गुणवत्ता में कमी, धुंध और कोहरा आम है तो दुनिया के बड़े शहरों में ग्रेप पाबंदिया तक लगाने को बाध्य होना पड़ रहा है। जनजीवन ही नहीं स्वास्थ्य तक प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर जब दिसंबर 2015 में पेरिस में दुनिया के देषों की कोप 21 के दौरान ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधी की रुपरेखा तय हुई और 4 नवंबर, 2016 को जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित दुनिया के देशों ने पेरिस समझौते पर क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाये तो समूची दुनिया में आशा का संचार हुआ है। आज पेरिस समझौते को दस साल पूरे हो चुके हैं और ओजोन परत के मामलें में तो दुनिया के देशों ने एक तरह से सफलता प्राप्त कर ली है। इस समय तुर्किया के अंताल्या में दुनिया के देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं तो दूसरी और यह दूसरा मौका है जब अमेरिका ने इस सम्मेलन से किनारा किया है। यह महज संयोग ही नहीं है अपितु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हठधर्मिता ही मानी जानी चाहिए की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में चीन के साथ प्रमुख देश होने के बावजूद अमेरिका ने पेरिस समझौते से किनारा कर लिया है। ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल 2020 में भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर अनावश्यक बोझ बताते हुए किनारा किया और 2021 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद 2021 में शामिल होने की घोषणा की पर ट्रम्प ने दूसरे कार्यकाल में 2026 में एक बार फिर किनारा कर लिया है। हांलाकि यह अमेरिका का गैर जिम्मेदारान कदम है और दुनिया के देषों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सारी दुनिया प्रभावित हो रही है। अकेले सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की ही बात करें तो सालाना 90-92 लाख लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु की गुणवत्ता 2.5 पीएम के स्तर पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 तक को बेहतरीन माना गया है तो 51 से 100 तक भी संतोषजनक की श्रेणी में माना जा सकता है। पर इससे अधिक और खासतौर से 300 से अधिक एक्यूआई अत्यधिक खतरनाक स्थिति माना गया है। आज हवा के जहरीली होने के कारण सबसे अधिक बच्चों और बुजुर्गों को दो चार होना पड़ता है। प्रदूषित हवा के चलते फेफडें, हृदय, स्ट्रोक और डिमेंशिया की बीमारी का विस्तार हो रहा है। अरबों रुपए इन बीमारियों के ईलाज में खर्च हो रहे हैं तो लाखों जाने प्रतिवर्ष इनके कारण जा रही है। यदि भारत की ही बात करें तो स्वास्थ्यकर मानकों के अनुकूल गुणवत्तायुक्त सांस लेने के हवा नहीं मिलने के कारण सालाना 6 से 8 लाख लोग फेफड़ो की बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं तो 15 से 20 लाख तक हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। स्ट्रोक से प्रभावित होने वालों की संख्या भी कम नहीं है और करीब 5 से 6 लाख लोग स्ट्रोक के अटेक से ग्रसित हो जाते हैं। यहां तक कि ढ़ाई से तीन लाख लोग डिमेंशिया के शिकार हो जाते हैं। यह हालात अपने आपमें चिंताजनक है। दुनियाभर की मानें तो एक करोड़ से भी अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण जनित रोगों से काल के मुंह में समा जाते हैं। केवल दवा आदि में ही अरबों डालर रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में यदि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके 2.5 पीएम स्तर पर लाने के ठोस प्रयास किये जाएं तो अरबों डॉलर ही नहीं अपितु लाखों जिंदगानी को बचाया जा सकता है। साफ हवा होगी तो जान लेवा बीमारियों से बचा जा सकेगा। स्वास्थ्य और देखभाल में होने वाले खर्चे को इकोनोमी को बूस्ट करने में काम में लिया जा सकेगा। अरबों रुपयों की बचत होगी तो अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा। दरअसल वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जैविक उर्जा साधन है। कारखानों व ईंधन के रुप में उपयोग होने वाली जैविक इंर्धन वायु को सर्वाधिक प्रदूषित कर रहा है। हांलाकि पराली, पटाखों और अन्य कारकों भी कारण माना जा रहा है। पॉवर सेक्टर, कृषि, उद्योग, प्राकृतिक घटनाओं व अन्य कारणों के साथ ही परिवहन यानी कि यातायात के साधनों में उपयोग होने वाला डीजल-पेट्रोल और निर्माण कार्यों और कचरा अपशिष्ट से वायु प्रदूषण फैल रहा है। हांलाकि रिन्यूवल एनर्जी और ई व्हीकल के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है पर अभी भी पॉवर सेक्टर, परिवहन वाहनो आदि में जैविक ईंधन की निर्भरता बहुत अधिक और चिंतनीय स्तर पर है। समय रहते इसमें सुधार आवश्यक है और इस दिषा में दुनिया के देशों को तेजी से योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। क्योंकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का यह अध्ययन केवल कुछ देशों या क्षेत्रों तक सीमित ना होकर दुनिया के 136 देशों के अध्ययन का परिणाम है और इसके नतीजे ना केवल दुनिया को चेताने वाले हैं अपितु समय रहते ठोस प्रयास करने की साफ साफ चेतावनी भी है।

विचार

केंद्र की यह एक सार्थक पहल हैः छावनियों में बुजुर्गों और बच्चों की व्यवस्था

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

किसी परिवार की वास्तविक खुशी तब पूरी होती है, जब घर के बुजुर्गों को अपनों का साथ मिले और बच्चों का बचपन सुरक्षित हाथों में हो। आज की व्यस्त जीवनशैली में इन दोनों जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना अनेक परिवारों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सैन्य छावनियों में बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह और बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर स्थापित करने तथा मौजूदा सुविधाओं के विस्तार का जो निर्णय लिया है, वह संवेदनशील सामाजिक सोच का परिचायक है। वस्तुतः यह पहल अपने भीतर परिवार की तीन पीढ़ियों की चिंता समेटे हुए है। एक ओर कामकाजी माता-पिता को बच्चों की सुरक्षित देखभाल का भरोसा मिलेगा, दूसरी ओर बुजुर्गों को जीवन के इस पड़ाव पर साथ, सम्मान और अपनत्व का वातावरण उपलब्ध होगा। रक्षा प्रतिष्ठानों की व्यवस्थाओं को सामाजिक कल्याण से जोड़ने वाला यह निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है। इस संबंध में कहना होगा कि भारतीय परिवार व्यवस्था में बुजुर्गों का अनुभव और बच्चों का भविष्य, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों का विस्तार हुआ है। पति-पत्नी दोनों के रोजगार से जुड़े होने के कारण बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय निकालना कठिन होता जा रहा है। दूसरी ओर, उम्रदराज माता-पिता को स्वास्थ्य संबंधी सहयोग, नियमित देखभाल और भावनात्मक संबल की आवश्यकता होती है। रोजगार, स्थानांतरण और व्यस्त दिनचर्या के बीच परिवारों के सामने इन जिम्मेदारियों को निभाने की चुनौती बढ़ी है। सैन्य परिवारों की परिस्थितियां इससे कुछ अधिक जटिल होती हैं। सेना के अधिकारियों और जवानों की तैनाती तथा स्थानांतरण के कारण परिवारों को बार-बार नई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है। ऐसे में छावनियों के भीतर बच्चों और बुजुर्गों के लिए संस्थागत सुविधाओं का विकास एक व्यावहारिक समाधान बन सकता है। इस दिशा में रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत हुआ समझौता महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम से इस पहल को प्रशासनिक और वित्तीय आधार मिला है।

इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। छावनी बोर्डों के अपने बजट से संचालित मौजूदा डे-केयर सेंटरों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन एवं रखरखाव में भी सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ ही नए केंद्र स्थापित करने और वर्तमान सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है। इससे छावनी बोर्डों की प्रशासनिक क्षमता और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। बच्चों के लिए डे-केयर सेंटरों की व्यवस्था आज के कामकाजी परिवारों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। माता-पिता जब अपने कार्यस्थल पर होते हैं, तब बच्चों की सुरक्षा, खानपान और दिनचर्या को लेकर उनकी चिंता स्वाभाविक है। छावनियों में विकसित होने वाले ये केंद्र बच्चों को सुरक्षित वातावरण, नियमित देखभाल, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरे बच्चों के साथ संवाद और सामूहिक गतिविधियां उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में भी सहायक होंगी। इससे माता-पिता को मानसिक राहत मिलेगी और वे अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों पर बेहतर ढंग से ध्यान दे सकेंगे। सैन्य परिवारों के लिए यह सुविधा विशेष उपयोगी होगी, जहां सेवा संबंधी दायित्वों के कारण पारिवारिक दिनचर्या प्रभावित होती रहती है। इस पहल का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृहों की व्यवस्था है। उम्र के साथ व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त संवाद, सामाजिक मेलजोल और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता बढ़ती है। जीवनभर परिवार और समाज के लिए योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के उत्तरार्ध में सम्मान और अपनत्व मिलना चाहिए। ऐसे केंद्रों में उन्हें समान आयु वर्ग के लोगों के साथ समय बिताने, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने और आवश्यक देखभाल प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। यहां यह भी समझना जरूरी है कि बुजुर्गों की जरूरतें दवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित नहीं होतीं। उनकी बात सुनने वाला कोई हो, उनके अनुभवों को महत्व मिले और आसपास अपनेपन का वातावरण हो, यह भी उनके सुखी जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। इन गृहों का संचालन इस भावना के साथ होना चाहिए कि वे परिवारों के सहयोगी बनें और बुजुर्गों के पारिवारिक संबंध निरंतर मजबूत रहें।

एक नजर

सारण में संकल्प संध्या का हुआ शुभारंभ, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नि :शुल्क रेमेडियल क्लासेज शुरू

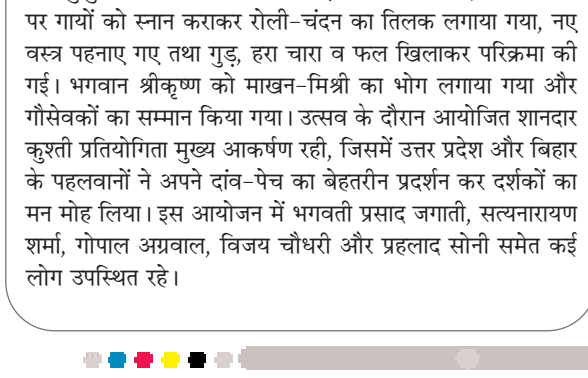


सारण,एजेंसी। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए एक विशेष पहल संकल्प संध्या यानी इवनिंग रेमेडियल क्लासेज का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत छपरा के जिला स्कूल में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत यह कक्षाएं 17 नवंबर से 31 मार्च 2027 तक प्रतिदिन शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक संचालित होंगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं इस पूर्णत: नि:शुल्क व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। इसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के साथ-साथ कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाएगी। विद्यार्थियों को होमवर्क में मदद के साथ आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष तैयारी कराई जाएगी। पठन-पाठन को प्रभावी बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जा रहा है। इन कक्षाओं में सरकारी शिक्षकों के अलावा सेवानिवृत्त आईएएस और अन्य अनुभवी अधिकारी स्वैच्छिक रूप से मार्गदर्शन करेंगे। सारण के डीईओ ने कहा कि इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को मुख्यधारा की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।

छपरा जंक्शन स्थित कोचिंग डिपो और रनिंग रूम का डीआरएम आशीष जैन ने किया निरीक्षण

सारण। वाराणसी मंडल के रेल प्रबंधक आशीष जैन ने अपने दो दिवसीय निर्धारित निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज छपरा कोचिंग डिपो, सिक लाइन, क्रू लॉबी और रनिंग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनुरक्षण कार्यों की गुणवत्ता, संरक्षा उपकरणों की कार्यशीलता, तकनीकी व्यवस्थाओं, स्वच्छता तथा कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सिक लाइन के विभिन्न स्टोर रूम, मशीन रूम, ऑयल रूम, विश्राम कक्षों एवं ईओटी क्रेनों की कार्यशीलता की जांच की। साफ-सुथरे रखरखाव पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने शीघ्र ही स्टाफ कैंटीन हेतु एक नया कक्ष तैयार कराने के निर्देश दिए। इसके पश्चात, वाशिंग पिट संख्या-01 पर खड़ी गाड़ी संख्या 15083 के रेक का संरक्षा निरीक्षण किया गया, जिसमें पहियों के व्यास, व्हील डिस्टेंस और ट्रेड वियर की निर्धारित मानकों के अनुरूप जांच हुई। उन्होंने एसबीसी पैनल, ट्रबलशूटिंग तथा ब्रेक पावर टेस्टिंग की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और कर्मचारियों को ओएचई चार्जिंग-डिस्चार्जिंग संबंधी संरक्षा प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक किया। डीआरएम ने क्रू लॉबी एवं रनिंग रूम में क्रू मैनेजमेंट व विश्राम व्यवस्था का जायजा लिया। लोको पायलटों और ट्रेन मैनेजरों से संवाद कर उन्होंने कार्य परिस्थितियों की जानकारी ली तथा भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पौष्टिकता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान वरिष्ठ मंडल इंजीनियर ब्रह्मानंद, कुंवर सिंह यादव, अशोक कुमार समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।

सारण के पिन्जरापोल गौशाला में धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी सह गौ पूजनोत्सव



सारण। छपरा के पिन्जरापोल गौशाला, हिरानीबाग करिंगा के प्रांगण में गोपाष्टमी के पावन अवसर पर गौ पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में धर्म, संस्कृति और पर्यावरण का अनूठा संगम देखने को मिला, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहा कि गौ माता इस धरती पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो श्वसन क्रिया में केवल ऑक्सीजन ही लेती और छोड़ती है। गोबर और गोमूत्र के माध्यम से भी यह पर्यावरण को ऑक्सीजन प्रदान करती है। सृष्टि के पांचों महाभूत (जल रूपी दूध, पृथ्वी रूपी गोबर, वायु रूपी गोमूत्र, अग्नि रूपी धगि और आकाश रूपी छाछ) गाय से प्राप्त होते हैं।

उन्होंने कहा कि जब घर-घर में गाय थीं, तब असाध्य रोग समाज को छू भी नहीं पाते थे। आज खेतों में पेस्टिसाइड के बजाय गोवंश आधारित प्राकृतिक खेती अपनाने से ही स्वास्थ्य और किसानी दोनों को बचाया जा सकता है। धार्मिक प्रसंग का जिक्र करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि जब भगवान कृष्ण छह वर्ष के हुए, तब उन्होंने मैया यशोदा और नंद बाबा से गाय चराने की इच्छा जताई थी। ऋषि शांडिल्य द्वारा दिए गए शुभ मुहूर्त पर गोपाष्टमी के दिन कान्हा को मोर मुकुट पहनाकर गोचारण के लिए भेजा गया था। इस पावन पर्व पर गायों को स्नान कराकर रोली-चंदन का तिलक लगाया गया, नए वस्त्र पहनाए गए तथा गुड़, हरा चारा व फल खिलाकर परिक्रमा की गई। भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाया गया और गौसेवकों का सम्मान किया गया। उत्सव के दौरान आयोजित शानदार कुश्ती प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण रही, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के पहलवानों ने अपने दांव-पेच का बेहतरीन प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस आयोजन में भगवती प्रसाद जगाती, सत्यनारायण शर्मा, गोपाल अग्रवाल, विजय चौधरी और प्रहलाद सोनी समेत कई लोग उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को करेंगे 'नीतीश सेतु' का लोकार्पण

पटना,एजेंसी। बिहार की आधारभूत संरचना को मजबूती देने वाली महत्वाकांक्षी कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल परियोजना पूरी हो गई है। अब यह पुल 'नीतीश सेतु' के नाम से जाना जाएगा। आगामी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस पुल का लोकार्पण कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुगम होने के साथ राज्य की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। गंगा नदी पर निर्मित यह छह लेन पुल आधुनिक इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके शुरू होने से पटना और वैशाली के बिदुपुर के बीच सीधा संपर्क मजबूत होगा। साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच दशकों से चली आ रही आवागमन संबंधी चुनौतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव भी कम होने की उम्मीद है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2012 में राज्य की तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने की थी। उसी वर्ष सितंबर में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आईडीए) ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके बाद फरवरी 2013 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की गई और कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) को परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पुल के एलाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण किया गया। अगस्त 2014 में केंद्र की राजग सरकार ने एशियाई विकास बैंक



(एडीबी) से ऋण सहायता की सिफारिश की। इसके बाद दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया। मार्च 2015 में मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में निर्माण कार्य को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। जुलाई 2015 में राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद अंतरराष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की गई और निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध कर परियोजना का काम शुरू हुआ।

इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) पद्धति से तैयार इस छह लेन पुल परियोजना पर कुल 5,571.69 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसमें एशियाई विकास बैंक ने 3,472.15 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी, जबकि बिहार सरकार ने 2,099.54 करोड़ रुपये का योगदान किया। परियोजना में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय एवं प्रशासनिक समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुल के चालू होने से राजधानी पटना और वैशाली के बीच यात्रा आसान होगी। इससे यात्रियों के समय और ईंधन की बचत होगी तथा उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से पटना पहुंचना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। परिवहन व्यवस्था में सुधार का सीधा लाभ कृषि उत्पादों की ढुलाई को भी मिलेगा। उत्तर बिहार की लीची, केला, मक्का और सब्जियों को पटना सहित देश के अन्य बड़े बाजारों तक कम समय में पहुंचाना आसान होगा। इसके अलावा कच्ची दरगाह-बिदुपुर कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स हब, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, 'नीतीश सेतु' बिहार की आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसके लोकार्पण से राज्य में आवागमन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

बोधगया में 21वें अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह की तैयारी तेज, 2 दिसंबर से जुटेंगे 25 हजार बौद्ध श्रद्धालु

पटना। भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया में 2 दिसंबर से दुनिया के विभिन्न देशों के हजारों बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और पर्यटक जुटेंगे। यहां 2 से 12 दिसंबर तक 21वें अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 25 हजार देशी-विदेशी लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस बार भारत मुख्य आयोजक देश की भूमिका निभाएगा। समारोह का उद्घाटन 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन और आयोजक संस्था ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा कई देशों से बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं और श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। संभावित भीड़ को देखते हुए आवासन, भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बोधगया स्थित विभिन्न बौद्ध मठों में इंतजाम किए जाएंगे। यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों की बौद्ध परंपराओं और संस्कृतियों को एक मंच पर लाएगा। 11 दिनों तक चलने वाले समारोह में भगवान बुद्ध के उपदेशों का पाठ करने के साथ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। समारोह का विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और श्रीलंका में भारत के राजदूत सहित कई विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है।

आयोजन के लिए बोधगया के ऐतिहासिक कालचक्र मैदान में विशाल टेंट पंडाल तैयार किया जाएगा। यहां धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। समारोह के धार्मिक और पारंपरिक कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी लाइट ऑफ बुद्धा धम्मा फाउंडेशन को सौंपी गई है। फाउंडेशन के निदेशक रंजन कुमार के अनुसार, बांगबो डिक्सी के नेतृत्व में महाबोधि मंदिर की सजावट, शोभायात्रा और श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार, जिला प्रशासन और फाउंडेशन के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नहर किनारे बांसबाड़ी में मिला 22 वर्षीय युवक का शव, इलाके में सनसनी

सुपौल। जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया बड़ी नहर किनारे महिचंदा साइफन से करीब 200 मीटर दक्षिण पश्चिमी छोर स्थित बांसबाड़ी में मंगलवार को 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।



शव मिलने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान कटैया माहे पंचायत के वार्ड संख्या-7 निवासी इंदू मंडल के पुत्र कृष्णा कुमार (22) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब एक बजे गांव की कुछ महिलाएं बांसबाड़ी में जलावन के लिए लकड़ी चुनने गई थीं। इसी दौरान उनकी नजर वहां पड़े एक युवक के शव पर पड़ी। महिलाओं ने तत्काल इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पिपरा थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने में जुट गई। कुछ ही देर में मृतक के पिता इंदू मंडल ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान अपने पुत्र कृष्णा कुमार के रूप में की। मृतक के पिता ने बताया कि सोमवार की रात करीब नौ बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सो गए थे। उन्हें जानकारी नहीं है कि कृष्णा कब घर से निकला। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र नशे का आदी था। उसके जेब से नशे से संबंधित सामग्री भी बरामद हुई है। इधर, युवक का शव बांसबाड़ी में मिलने के बाद हत्या कर शव को वहां फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, युवक की मौत कैसे हुई, इसका वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी राजीव रंजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि शव की पहचान कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सुपौल भेजा जा रहा है। पुलिस घटना की तहकीकात कर रही है। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी है।

लालू परिवार की इच्छा पर नहीं, बिहार के विकास में योगदान पर होता है पुलों का नामकरण : संजय सरावगी

पटना। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने पर विपक्ष की बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लालू परिवार की राजनीतिक इच्छा और वास्तविकता में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार के मन की दबी हुई इच्छा को रोहिणी आचार्य ने अपने बयान के माध्यम से जाहिर कर दिया है। उनकी इच्छा है कि जिस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, उसका नाम लालू यादव के नाम पर रखा जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी सजायाफ्ता व्यक्ति के नाम पर किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना का नामकरण किया जाना उचित है?

संजय सरावगी ने कहा कि लालू परिवार और राजद के नेता इस मुद्दे पर अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक भ्रम फैलाना है। कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल की परिकल्पना से लेकर इसके निर्माण तक लालू परिवार का कहीं कोई योगदान नहीं रहा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना केंद्र और बिहार सरकार के सहयोग से साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि एडीबी से इस परियोजना के लिए ऋण प्राप्त करने में केंद्र सरकार गारंटर बनी। एनडीए सरकार के कार्यकाल में बिहार में कर संग्रह बढ़ा, जिससे राज्य सरकार भी विकास परियोजनाओं में अपना वित्तीय योगदान देने में सक्षम हुई। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इस पुल का निर्माण आगे बढ़ा है। उस समय पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी ललन सिंह के पास थी।



तेजस्वी यादव का इस परियोजना से कोई लेना-देना नहीं रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जंगलराज से सुशासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में सड़क, पुल-पुलिया और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया। बिहार की सरकार ने इन्हीं योगदानों को सम्मान देते हुए छह लेन पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखने का निर्णय लिया है। यह बिहार के विकास में उनके योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस फैसले से बिहार की जनता में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर के बिहार दौरे को लेकर सरावगी ने कहा कि 20 नवंबर को एनडीए सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 21 नवंबर को बिहार आने वाले है। उनका यह दौरा राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो उन्हें सुनने के लिए लाखों लोग जुटते हैं। इस दौरान कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। प्रधानमंत्री कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल बिहार की जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पुल बिहार की बदलती तस्वीर, मजबूत होती कनेक्टिविटी और विकास के प्रति एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनेगा। इससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर वैशाली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, तैयारियों की समीक्षा की

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को प्रस्तावित बिहार दौरे और हाजीपुर में होने वाली जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी आज वैशाली पहुंचे। उन्होंने राजापाकर प्रखंड के जाफरपट्टी में भाजपा के संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक मंगल पांडेय के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने सभा स्थल एवं हैलीपैड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर आम लोगों में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने बिहार की जनता, विशेषकर वैशाली और आसपास के जिलों के लोगों से 21 नवंबर के कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को वर्तमान एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपना गौरव बढ़ा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री , पूर्व मुख्यमंत्री एवं एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की निरंतर प्रगति और बिहार में



विकास कार्यों को मिल रही गति के कारण लोगों में उनके कार्यक्रम को लेकर विशेष उत्साह है। 21 नवंबर को हाजीपुर में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जनसभा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगी। इसमें बिहार के विभिन्न हिस्सों से लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तत्परता से जुटे हैं। वैशाली सहित आसपास के जिलों में लोगों के बीच कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। उन्होंने सभी लोगों से इस जनसभा में शामिल होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने की अपील की।

सारण में सड़क खुदाई से पहले आइओसीएल अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य : जिलाधिकारी सारण

सारण। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब न होने दें। बैठक का केंद्रबिन्दु सड़क सुरक्षा रहा। जिलाधिकारी ने पथ निर्माण, विद्युत, आरडीडी और आरसीडी सहित सभी कार्यकारी एजेंसियों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि किसी भी सड़क की खुदाई से पूर्व आइओसीएल के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति पूर्णत: अनिवार्य होगी। आइओसीएल द्वारा अपने भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क और मैप्स साझा किए गए हैं, ताकि बिना अनुमति खुदाई से पाइपलाइन क्षति और गैस रिसाव जैसी गंभीर दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

बडको और सभी नगर निकायों को भी इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके साथ ही सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी से जुड़े लंबित मामलों का तत्परतापूर्वक निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत आज से विद्यालय स्तर पर निर्वाचन जागरूकता अभियान प्रारंभ करने, मतदाता सूची में जेंडर रेशियो सुधारने और 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग के युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया। इसमें जीविका दीदियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को भी कहा गया। सामाजिक सुरक्षा के तहत कबीर अंत्येष्टि योजना की समीक्षा के दौरान सारण जिले की 80 पंचायतों में शून्य प्रविष्टि मिलने पर डीएम ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बीडीओ और पंचायत सचिवों को इसकी तत्काल समीक्षा करने का निर्देश दिया। राजस्व कार्यों के तहत परिमार्जन, दाखिल-खारिज, जनता दरबार, राशन कार्ड और 'अभियान बसेरा' के माध्यम से भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने के कार्यों में तेजी लाने पर विशेष बल दिया गया। कायाकल्प योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग के शेष बचे कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। इसके अलावा, जिला गंगा समिति की बैठक में सोनपुर मेला क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन और एसटीपी, एमआरएफ व कंपोस्ट यूनिट के प्रस्तावों की स्थलीय जांच कराकर व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

एक नजर

खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की विकसित होती है भावना : प्रो. आशीष खरे

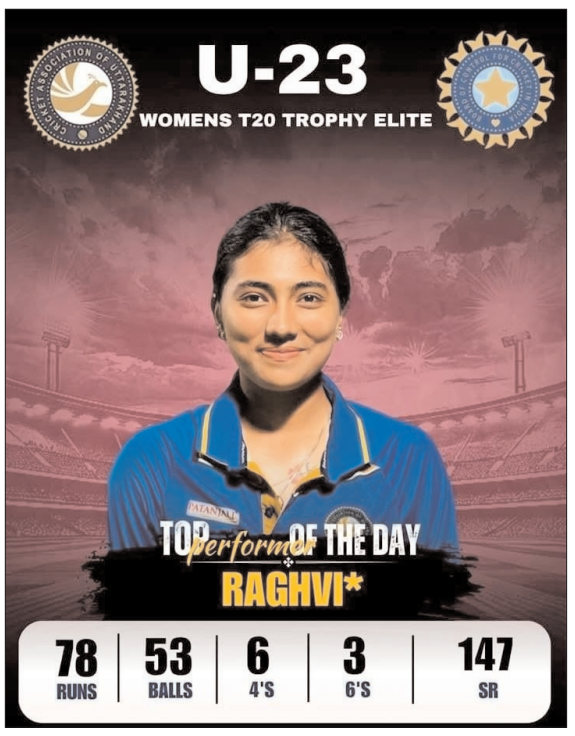


प्रयागराज,एजेंसी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मंगलवार को वार्षिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कुलसचिव प्रो. आशीष खरे ने किया। प्रतियोगिता अगले दो दिनों तक चलेगी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। पहले दिन साइकिलिंग, शतरंज और दौड़ सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के पहले दिन विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय परिसर में साइकिलिंग के अंतिम मुकाबले आयोजित किए गए। इसमें विद्यार्थियों के अलावा विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी भी शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दोपहर में विद्यार्थियों के बीच शतरंज और दौड़ प्रतियोगिताएं हुईं। स्पोर्ट्स बोर्ड में शतरंज के मुकाबले आयोजित किए गए, जबकि एमसीसी मैदान में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ के साथ 4म100 मीटर रिले दौड़ कराई गई। प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉ. पंकज शर्मा और सह खेल निदेशक डॉ. सर्वश्रेष्ठ धम्मी ने बताया कि पहले दिन सभी प्रतिभागियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के आगामी दो दिनों में भी विभिन्न खेल मुकाबले आयोजित किए जाएंगे।

धीमी ओवर गति पर पाकिस्तान और श्रीलंका पर जुर्माना, डब्ल्यूटीसी अंक भी कटे

रावलपिंडी,एजेंसी। पाकिस्तान और श्रीलंका पर रावलपिंडी में खेले गए दो मैचों की आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) सीरीज के पहले टेस्ट में धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मैच फीस का 25 प्रतिशत और श्रीलंका के खिलाड़ियों की मैच फीस का 50 प्रतिशत काटा जाएगा। इसके साथ ही दोनों टीमों के डब्ल्यूटीसी खाते से एक-एक अंक भी कम किया गया है। आईसीसी के एमिरेट्स एलीट पैनल के मैच रेफरी डीन कॉस्कर ने यह कार्रवाई की। समय की छूट को समायोजित करने के बाद पाकिस्तान निर्धारित समय में पांच ओवर और श्रीलंका 15 ओवर पीछे पाया गया। आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने पर खिलाड़ियों की मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, जुर्माने की अधिकतम सीमा मैच फीस का 50 प्रतिशत है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और श्रीलंका के कप्तान कुसल मेंडिस ने अपनी-अपनी टीमों की गलती स्वीकार करते हुए प्रस्तावित सजा मान ली। इसके चलते औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। मैदान पर मौजूद अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक और रॉड टकर, तीसरे अंपायर अल्लाहुद्दीन पालेकर तथा चौथे अंपायर फैसल अफरीदी ने धीमी ओवर गति के आरोप लगाए थे।

उत्तराखंड की अंडर-23 महिला टीम ने चंडीगढ़ को 114 रन से हराया



देहरादून। बीसीसीआई महिला अंडर-23 टी-20 ट्रॉफी एलीट में उत्तराखंड की टीम ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ को 114 रन से करारी शिकस्त दी। मुकाबले में उत्तराखंड की बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया, वहीं गेंदबाजों ने भी प्रतिद्वंद्वी टीम को दबाव में रखते हुए बड़ी जीत सुनिश्चित की। इस जीत को राज्य की महिला क्रिकेट के लिए उत्साहजनक संकेत माना जा रहा है। युवा खिलाड़ियों के लगातार बेहतर प्रदर्शन से उत्तराखंड की टीम की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और प्रतिभा का पता चलता है। यह सफलता खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही राज्य में महिला क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद भी जगाती है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) की सचिव किरण रौतेला वर्मा ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि अंडर-23 खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन गर्व का विषय है। 114 रन की जीत उनकी मेहनत, समर्पण और टीम भावना को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां लगातार साबित कर रही हैं कि राज्य महिला क्रिकेट में नई ऊंचाइयां हासिल करने की क्षमता रखता है। उन्होंने पूरी टीम, कोचिंग स्टाफ और सहयोगी सदस्यों को बधाई देते हुए भरोसा दिलाया कि सीएयू खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग देता रहेगा।

आईपीएल की सभी 10 टीमों ने जारी की रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची, कई बड़े नाम बाहर



नई दिल्ली,एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की सभी 10 फ्रेंचाइजी ने आगामी सत्र के लिए अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। इस बार कई टीमों ने अपने दल में बड़े बदलाव किए हैं। महेंद्र सिंह धोनी, ट्रेंट बोल्ट, ट्रैविस हेड, मिचेल स्टार्क और अजिंक्य रहाणे जैसे चर्चित नाम रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं। वहीं, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों के ट्रेड के जरिए टीम बदलने से भी समीकरण बदले हैं।

टीमों की ओर से जारी सूची इस प्रकार है—

1. चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)

रिलीज खिलाड़ी: एमएस धोनी, अमन खान, डियान फॉरेस्टर, कुलदीप यादव, मैकनील नोरोन्हा, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, आकाश मधवाल, प्रशांत वीर, स्पेंसर जॉनसन, जैक फॉल्क्स, खलील अहमद (ट्रेड आउट), नाथन एलिस (ट्रेड आउट)।

रिटेन खिलाड़ी: ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, राहुल चाहर, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, रामकृष्ण घोष, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, लियाम लिविंगस्टोन (ट्रेड इन), जैक एडवर्ड्स (ट्रेड इन)।

2. मुंबई इंडियंस (एमआई)

रिलीज खिलाड़ी: ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम गजनफर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, मोहम्मद इजहार, दानिश मालवर, मयंक मार्कंडे, मयंक रावत, महिपाल लोमरोर, रॉबिन मिंज, रुचित अहिर, कृष भगत, हार्दिक पांड्या (ट्रेड आउट)।

रिटेन खिलाड़ी: रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, नमन धीर, रयान रिकेल्टन, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन डी कॉक, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दुल ठाकुर, राज बावा, मिचेल सैंटनर, अश्वनी कुमार, रघु शर्मा, अर्शदीप सिंह (ट्रेड इन)।

3. दिल्ली कैपिटल्स (डीसी)

रिलीज खिलाड़ी: मिचेल स्टार्क, नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, पथुम निसांका, बेन डकेट, करुण नायर, साहिल पारख, दुश्मंथा चमीरा, रेहान अहमद, अजय मंडल, टी. नटराजन (ट्रेड आउट), कुलदीप यादव (ट्रेड आउट)।

रिटेन खिलाड़ी: अक्षर पटेल, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, औकिब नबी, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, काइल जैमीसन, ऋषभ पंत (ट्रेड इन), जीशान अंसारी (ट्रेड इन)।

4. लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी)

रिलीज खिलाड़ी: आवेश खान, मैथ्यू ब्रीट्जके, एनरिक नॉर्टजे, जॉर्ज लिंडे, वानिंदु हसरंगा, नमन तिवारी, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत (ट्रेड आउट), मोहम्मद शमी (ट्रेड आउट), एम. सिद्धार्थ (ट्रेड आउट)।

रिटेन खिलाड़ी: मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, जोश इंग्लिस, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, मयंक यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, अर्शिन कुलकर्णी, कुलदीप यादव (ट्रेड इन), सैम करन (ट्रेड इन)।

5. पंजाब किंग्स (पीबीकेएस)

रिलीज खिलाड़ी: नेहाल वढेरा, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल ओवेन, पायला अविनाश, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, अर्शदीप सिंह (ट्रेड आउट)।

रिटेन खिलाड़ी: श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मुशीर खान, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, सूर्यांश शेडगे, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस, यश ठाकुर, व्यशाक विजयकुमार, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, हरनूर सिंह, हार्दिक पांड्या (ट्रेड इन)।

6. राजस्थान रॉयल्स (आरआर)

रिलीज खिलाड़ी: शिमरोन हेटमायर, एडम मिल्ने, क्वेना मफाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, युधवीर सिंह, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, इमानजोत चहल, सैम करन (ट्रेड आउट)।

रिटेन खिलाड़ी: रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, नांद्रे बर्गर, शुभम दुबे, अमन राव, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, रवि बिश्नोई, यश राज पुंजा, जोफ्रा आर्चर, बृजेश शर्मा, संदीप शर्मा, सुशांत मिश्रा, मोहम्मद शमी (ट्रेड इन), एम. सिद्धार्थ (ट्रेड इन)।

7. सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच)

रिलीज खिलाड़ी: ट्रैविस हेड, कामिंदु मेंडिस, जयदेव उनादकट, दिलशान मदुशंका, ओंकार टारमले, अमित कुमार, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्जी, डेविड पेन, आरएस अम्बरीश, हर्षल पटेल (ट्रेड आउट), जीशान अंसारी (ट्रेड आउट), लियाम लिविंगस्टोन (ट्रेड आउट), जैक एडवर्ड्स (ट्रेड आउट)।

रिटेन खिलाड़ी: पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान मलिंगा, ब्रायडन कार्स, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, क्रेन्स फुलेत्रा, टी. नटराजन (ट्रेड इन), खलील अहमद (ट्रेड इन), नाथन एलिस (ट्रेड इन)।

8. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी)

रिलीज खिलाड़ी: जैकब बेथेल, रिचर्ड ग्लीसन, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, विहान मल्होत्रा, स्वप्निल सिंह।

रिटेन खिलाड़ी: रजत पाटीदार, विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह, रसिख सलाम, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्तवाल, कनिष्क चौहान, यश दयाल।

9. गुजरात टाइटंस (जीटी)

रिलीज खिलाड़ी: ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड, कुलवंत खेजरोलिया, शाहरुख खान, कॉनर एस्टरहुइजन, पृथ्वीराज यारा।

रिटेन खिलाड़ी: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, टॉम बैंटन, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, आर. साई किशोर, मानव सुथार, राशिद खान, जयंत यादव, जेसन होल्डर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, अरशद खान, निशांत सिंधु, हर्षल पटेल (ट्रेड इन)।

10. कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर)

रिलीज खिलाड़ी: अजिंक्य रहाणे, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी, दक्ष कामरा, लुवनित सिसोदिया, मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, नवदीप सैनी, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, तेजस्वी सिंह, उमरान मलिक।

रिटेन खिलाड़ी: कैमरन ग्रीन, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, फिन एलन, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, टिम साइफर्ट, सार्थक रंजन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी।

धोनी ने आईपीएल को कहा अलविदा, अब चेन्नई के बनेंगे मेंटर



नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खिलाड़ी के रूप में अपने करियर को विराम दे दिया है। वह अब चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के मेंटर की भूमिका निभाएंगे। टीम ने 2027 सत्र से पहले उनके नई जिम्मेदारी संभालने की पुष्टि की है। सीएसके के मालिक एन. श्रीनिवासन ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए एक आधिकारिक बयान में कहा कि धोनी हमेशा टीम की पहचान का हिस्सा रहेंगे और चेन्नई सुपर किंग्स ही उनका घर रहेगा। यह घोषणा आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की समयसीमा समाप्त होने से कुछ घंटे पहले की गई।

मेंटर के रूप में धोनी टीम के नए सहयोगी स्टाफ का हिस्सा होंगे। इस स्टाफ की अगुआई जहीर खान मुख्य कोच के रूप में करेंगे। उन्होंने स्टीफन फ्लेमिंग की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है। धोनी और फ्लेमिंग की जोड़ी ने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच आईपीएल खिताब और दो चैंपियंस लीग टी20 ट्रॉफी दिलाई थीं। धोनी के योगदान को याद करते हुए श्रीनिवासन ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के बिना चेन्नई सुपर किंग्स की कल्पना नहीं की जा सकती। करीब दो दशकों से दोनों का साथ रहा है। इस दौरान टीम ने जीत, हार और कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि 2008 में धोनी को टीम का हिस्सा बनाने का फैसला उनके सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। धोनी की उपलब्धियों के साथ उनका व्यक्तित्व भी उन्हें खास बनाता है। धोनी 2026 आईपीएल सत्र में टीम का हिस्सा होने के बावजूद एक भी मुकाबला नहीं खेले थे। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में कुल 278 मैच खेले और 5439 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 38.30 और स्ट्राइक रेट 137.46 रहा। उनके नाम 24 अर्धशतक और 264 छक्के दर्ज हैं। राइजिंग पुणे सुपरजायंट के साथ दो सत्र बिताने के अलावा उनका पूरा आईपीएल करियर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहा। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रबंध निदेशक केएस विश्वनाथन ने कहा कि धोनी की क्रिकेट उपलब्धियां हर प्रशंसक की यादों में हमेशा रहेंगी लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह चेन्नई के लोगों के अपने बन गए। उन्होंने कहा कि धोनी की विरासत केवल ट्रॉफियों तक सीमित नहीं है बल्कि टीम को जीत दिलाने के उनके तरीके में भी दिखाई देती है। मैदान पर उन्हें पीली जर्सी में नहीं देख पाना प्रशंसकों के लिए निराशाजनक होगा लेकिन उनका मार्गदर्शन टीम को मिलता रहेगा। धोनी ने अपना आखिरी आईपीएल मुकाबला 2025 सत्र में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला था। इस मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था।

प्रीमियर लीग : लिवरपूल के खिलाफ पहले मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड की कमान संभालेंगे पोचेतीनो

लंदन। इंग्लिश प्रीमियर लीग के 2026-27 सत्र के 11वें सप्ताह में कई अहम मुकाबले खेले जाएंगे। सबसे ज्यादा नजरें लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच होने वाले मुकाबले पर रहेंगी, जिसमें मॉरिसियो पोचेतीनो पहली बार मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुख्य कोच के रूप में टीम की कमान संभालेंगे। आर्सेनल के पास अपने शुरुआती 11 मैचों में 10 जीत हासिल करने वाली लीग की केवल पांचवीं टीम बनने का मौका होगा। एस्टन विला के कोच उनाई एमरी भी प्रीमियर लीग में क्लब के लिए अपना 150वां मुकाबला पूरा करेंगे। दूसरी ओर, मैनचेस्टर सिटी की भिड़ंत फुलहम से होगी। सिटी ने सभी प्रतियोगिताओं में फुलहम के खिलाफ लगातार 20 मुकाबले जीते हैं, जो इंग्लिश फुटबॉल में एक टीम के खिलाफ किसी दूसरी टीम की सबसे लंबी जीत की श्रृंखला है। इप्सविच टाउन का सामना टॉटेनहम हॉटस्पर से होगा। इप्सविच पिछले 29 लीग मुकाबलों में कोई भी मैच क्लीन शीट के साथ खत्म नहीं कर सका है। चेल्सी भी जीत की राह पर लौटने की कोशिश करेगी।

मैनचेस्टर सिटी बनाम फुलहम

मैनचेस्टर सिटी ने फुलहम के खिलाफ सभी प्रतियोगिताओं में अपने पिछले 20 मुकाबले जीते हैं। इनमें लीग के लगातार 17 मैच शामिल हैं। यह इंग्लिश फुटबॉल में किसी एक टीम के खिलाफ दूसरी टीम की सबसे लंबी जीत की श्रृंखला है। फुलहम ने सिटी के खिलाफ अपने पिछले 32 लीग मुकाबलों में हर बार गोल खाया है। इस दौरान सिटी ने कुल 80 गोल किए हैं। हालांकि, इस सत्र में सिटी अपने पिछले तीन लीग मैच हार चुकी है, जबकि फुलहम पिछले चार मुकाबलों से अपराजित है। उसने दो मैच जीते और दो ड्रॉ खेले हैं।

एस्टन विला बनाम सुंदरलैंड

एस्टन विला के कोच उनाई एमरी प्रीमियर लीग में क्लब के लिए अपना 150वां मुकाबला संभालेंगे। उनके नेतृत्व में विला ने 76 मैच जीते, 33 ड्रॉ खेले और 40 मुकाबले गंवाए हैं। मार्टिन ओ'नील के बाद वह विला के लिए 150 प्रीमियर लीग मैचों में कोचिंग करने वाले दूसरे प्रबंधक होंगे। इस सत्र में विला के निकोलस जैक्सन ने छह गोल किए हैं। उनसे अधिक गोल केवल एर्लिंग हालैंड (नौ) और अलेक्जेंडर इसाक (सात) ने किए हैं।

बोर्नमाउथ बनाम नॉटिंघम फॉरेस्ट

बोर्नमाउथ ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ अपने सभी आठ लीग मुकाबलों में हार से बचाव किया है। इनमें चार जीत और चार ड्रॉ शामिल हैं। टीम पहली बार शीर्ष लीग में लगातार पांच मुकाबले जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेगी। वर्ष 2026 में प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने 67, मैनचेस्टर सिटी ने 59 और ब्राइटन एंड होव एल्बियन ने 50 अंक जुटाए हैं। बोर्नमाउथ 49 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। इस सत्र में बोर्नमाउथ के इवानिल्सन ने पांच गोल और चार असिस्ट सहित कुल नौ गोल योगदान दिए हैं। उनसे अधिक गोल योगदान किसी अन्य खिलाड़ी का नहीं है।

चेल्सी बनाम लीड्स यूनाइटेड

चेल्सी ने सभी प्रतियोगिताओं में लीड्स के खिलाफ अपने पिछले 10 घरेलू मुकाबलों में से आठ जीते हैं। हालांकि, लीड्स ने पिछले सत्र में दोनों टीमों के बीच हुए लीग मुकाबलों में हार से बचाव किया था। लीड्स ने इस सत्र में लीग के दौरान केवल आठ गोल खाए हैं। इस मामले में आर्सेनल (पांच) और ब्राइटन (सात) उससे बेहतर हैं। लीड्स के गोलकीपर जेम्स ट्रैफर्ड का बचाव प्रतिशत 81.4 है, जो लीग में सर्वश्रेष्ठ है। पिछले सत्र की शुरुआत से जाओ पेड्रो के शुरुआती एकादश में रहने पर चेल्सी ने लीग में औसतन प्रति मैच 1.8 गोल किए हैं। वहीं, उनके शुरुआती एकादश में नहीं होने पर टीम का औसत घटकर 0.9 गोल प्रति मैच रह जाता है।

कोवेंट्री सिटी बनाम क्रिस्टल पैलेस

कोवेंट्री ने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ अपने छह प्रीमियर लीग मुकाबलों में से केवल एक गंवाया है। उसने दो मैच जीते और तीन ड्रॉ खेले हैं। दोनों टीमें मार्च 2012 के बाद पहली बार किसी प्रतियोगिता में आमने-सामने होंगी। क्रिस्टल पैलेस ने इस सत्र में 10 लीग मैचों में 24 गोल खाए हैं। 1980-81 सत्र के बाद यह इस स्तर पर टीम का सबसे खराब प्रदर्शन है।

विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

इंदौर,एजेंसी। मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रही आईबीएसएफ विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के मुख्य दौर में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। मंगलवार को खेले गए मुकाबलों में 29 बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी, कमल चावला, मनन चंद्रा और श्रीकृष्ण सूर्यनारायण ने प्रतिद्वंद्वियों को शिकस्त दी। महिला वर्ग में गत विजेता अनुपमा रामचंद्रन के साथ इंदौर की अमी कमानी ने भी पहले मुकाबले में जीत दर्ज की। भारतीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश बिलियर्ड्स एवं स्नूकर संघ के तत्वावधान में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें दुनिया के 48 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों को 12 समूहों में बांटा गया है। प्रत्येक समूह में चार खिलाड़ी राउंड रॉबिन आधार पर मुकाबले खेलेंगे। हर समूह से शीर्ष दो खिलाड़ी अगले चरण में पहुंचेंगे।

मंगलवार को खेले गए मुकाबलों में भारत के दिग्गज खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने फिलीपींस के माइकल मेंगोरियो को 4-1 से पराजित किया। अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित आडवाणी ने शुरुआती दोनों फ्रेम जीतकर बढ़त बनाई और अंत तक अपना दबदबा कायम रखा। ग्रुप-एल में यह उनकी पहली जीत रही। ग्रुप-ई में मनन चंद्रा ने हांगकांग के रयान ली को 4-2 से हराया। वहीं ग्रुप-बी में श्रीकृष्ण सूर्यनारायण ने कुवैत के अब्दुल्ला अल युसुफ को सीधे चार फ्रेम में 4-0 से शिकस्त दी। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कमल चावला ने जर्मनी के क्रिश्चियन रिक्टर को 4-1 से हराकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। हुसैन खान ने भी ग्रुप-एफ के मुकाबले में सिंगापुर के सनी वांग को 4-1 से मात दी। हालांकि, भारतीय खिलाड़ी केतन चावला को ग्रुप-सी में हांगकांग के वांग यूचेन के हाथों 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। केतन ने हाल ही में चीन में आयोजित विश्व टीम चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय खिलाड़ियों के बीच भी कई मुकाबले रोचक रहे। रयान राजमी ने फ्रांस के निकोलस मोर्ट्रक्स को 4-3 से हराया। मुकाबला 3-3 की बराबरी पर पहुंचने के बाद राजमी ने निर्णायक फ्रेम अपने नाम किया। ग्रुप-ए में पारस गुप्ता ने उजैर खान को भी 4-3 से पराजित किया। ग्रुप-जी में क्रिश गुरबक्शानी ने लक्ष्मण रावत को 4-1 से हराया। दूसरी ओर ग्रुप-बी में हांगकांग के टैम युन फंग ने भारत के ध्रुव पटेल को 4-3 से शिकस्त दी। महिला वर्ग में गत विजेता अनुपमा रामचंद्रन ने फ्रांस की ओफेली लावल को 2-0 से हराकर खिताब बचाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। इंदौर की अमी कमानी ने भी घरेलू दर्शकों के सामने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत की 16 वर्षीय अफिफा फखरूद्दीन को 2-0 से शिकस्त दी। अन्य मुकाबलों में फिलीपींस की कार्मिले बुहाट ने आयरलैंड की एला ओ'कॉनर को और भारत की किर्थना पांडियान ने पूजा गलुंडिया को 2-0 से हराया। रवीना उमादेवी ने सान्वी शाह को 2-1 से पराजित किया, जबकि हांगकांग की सो मन यान ने आयरलैंड की मार्गरेट के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की।

एक नजर

यूरोपीय संघ ने भारतीय इस्पात पर लगाया 9.5 प्रतिशत एंटी-डंपिंग शुल्क

ब्रसेल्स,एजेंसी। यूरोपीय संघ (ईयू) ने भारत, जापान, ताइवान, तुर्किये और वियतनाम से आयात होने वाले कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों पर 27.9 प्रतिशत तक एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, ये उत्पाद यूरोपीय बाजार में अनुचित रूप से कम कीमतों पर बेचे जा रहे थे। नए शुल्क 17 नवंबर से लागू होंगे। भारत की जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और अन्य कंपनियों के उत्पादों पर 9.5 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। वहीं, जापानी इस्पात कंपनियों पर 27.9 प्रतिशत और ताइवान की प्रमुख कंपनियों पर मुख्य रूप से 20.7 प्रतिशत शुल्क लगेगा। सहयोग नहीं करने वाली कंपनियों के लिए यह दर 27 प्रतिशत तय की गई है। वियतनाम की कंपनियों पर 16 प्रतिशत, जबकि तुर्किये की इस्पात कंपनियों पर 3 से 7.8 प्रतिशत तक शुल्क लगाया गया है। जापान की निप्पॉन स्टील और जेएफई स्टील तथा ताइवान की चाइना स्टील कॉरपोरेशन प्रभावित कंपनियों में शामिल हैं। यूरोपीय इस्पात उद्योग संघ यूरोफर ने 2025 में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। संगठन का कहना है कि कम कीमत पर होने वाला आयात यूरोप के घरेलू उत्पादन और रोजगार के लिए खतरा बन रहा है। उसके मुताबिक, नए शुल्क से बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करने में मदद मिलेगी। कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील का इस्तेमाल कार, विमान, घरेलू उपकरण बनाने और निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होता है। यूरोपीय संघ में इस बाजार का मूल्य करीब 23.2 अरब यूरो है, जबकि इन पांच देशों से होने वाला आयात लगभग 1.78 अरब यूरो का है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, भारत में लौह अयस्क की कीमतों को प्रभावित करने वाले सरकारी उपायों के कारण घरेलू इस्पात कीमतों में विकृति आई है। वहीं, ताइवान में चीन से सस्ते इस्पात के बढ़ते आयात ने स्थानीय कीमतों को नीचे धकेला है। इसी आधार पर आयोग ने दोनों देशों की घरेलू बिक्री कीमतों में संशोधन कर शुल्क की गणना की।

बलोचिस्तान में जंगल से गायब दो चरवाहे बच्चे मृत मिले, सीटीडी अधिकारी तीन लोगों को घर से उठा ले गए



इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। बलोचिस्तान प्रांत के शिरानी जिले में शेकर होटल के पास पहाड़ी जंगल से सोमवार दोपहर अचानक गायब हुए दो छोटे चरवाहे बच्चे मंगलवार सुबह मरे हुए मिले। इस अलावा तीन लोगों को घर से अधिकारी उठा ले गए हैं। तीनों को फिलहाल कहां रखा गया है, यह साफ नहीं हो सका है। द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती रिपोर्ट में बच्चों की लाशों के पास ग्रेनेड या गोली जैसी कोई संदिग्ध चीज मिली है। हालांकि, बच्चों की मौत का असली कारण अभी तक पता नहीं चला है, न ही कोई पक्की पुष्टि हुई है। इनमें एक बच्चे की पहचान यतीम अली खान के तौर पर हुई है। दूसरे की पहचान जुमा गुल के बेटे के तौर पर हुई है। इस बीच प्रांत के अलग-अलग इलाकों से तीन लोगों के जबरदस्ती गायब कर देने के मामले सामने आए हैं। बताया गया है कि 15 नवंबर को क्वेटा के मुस्तफाबाद इलाके के अब्दुल सत्तार के पुत्र 20 वर्षीय जैनुल आबेदीन को उसके घर से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) के अधिकारी उठा ले गए। रात 11 बजे क्वेटा के किलजियो इलाके के मुहम्मद असलम के बेटे 15 साल के मुराद बलोच को भी सीटीडी के कर्मचारी उठा ले गए। रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर को ही केच जिले के तरबत इलाके के केच टावर निवासी 25 वर्षीय तलाल मंजूर को डेथ स्क्वाड के अधिकारियों ने दोपहर 3 बजे हिरासत में लिया। इन तीनों को कहां रखा गया है, यह साफ नहीं हो सका है। उधर, 22 अक्टूबर से गायब साबी जिले के सांगन इलाके के अख्तर मोहम्मद का बेटा गुल अहमद 12 नवंबर को मिल गया है।

नेपाल के पूर्व पीएम ओली का आरोप, हिंसा व आगजनी के जरिए हटाई गई थी उनकी सरकार

काठमांडू। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधपानमंत्री शर्मा ओली ने दावा किया है कि उनकी अगुवाई वाली सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं बल्कि बल प्रयोग, आगजनी और लूटपाट के जरिए सत्ता से हटाया गया था। काठमांडू में अखिल नेपाल किसान महासंघ की बैठक को संबोधित करते हुए ओली ने कहा कि उपद्रवियों ने राज्य की संस्थाओं और सरकारी तंत्र को निष्क्रिय एवं प्रभावहीन बना दिया था। इसी स्थिति में उन्हें और उनके सहयोगियों को सरकार छोड़नी पड़ी। ओली ने यह भी कहा कि जेन-जी आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं की अब तक निष्पक्ष जांच नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा गठित जांच आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आंदोलन के दौरान हुई आगजनी तथा लूटपाट की निष्पक्ष जांच करने के बजाय उन्हें और उनके सहयोगियों को दोषी ठहराने के उद्देश्य से काम किया। ओली ने कहा, 'हमें सत्ता से बाहर किया गया लेकिन यह लोकतांत्रिक रास्ते से नहीं हुआ। राज्य की संस्थाओं को निष्क्रिय और प्रभावहीन बनाकर बल प्रयोग, आगजनी और लूटपाट के जरिए हमें सरकार से हटाया गया। लोगों की हत्या करवा कर सत्ता पर कब्जा किया गया। आखिर लोगों को किसने मारा? गोलियां किसने चलाईं? जांच आयोग बनाए गए और स्थायी मानवाधिकार आयोग भी मौजूद है। लेकिन वास्तव में कोई जांच नहीं हुई। शायद आयोगों का उद्देश्य जांच करना ही नहीं था। उनका मकसद केपी ओली को दोषी ठहराना था। उन्होंने विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को नियंत्रित और विनियमित करने के प्रयास को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उस निष्कर्ष पर भी आपत्ति जताई, जिसमें तत्कालीन संचार मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ओली ने प्रतिनिधि सभा के विघटन से संबंधित मामले में फैसला सुनाने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जांच आयोगों ने खुद यह निष्कर्ष निकाला है कि गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। न तो तत्कालीन प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री ने गोली चलाने का आदेश दिया था। विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों के नियमन का बचाव करते हुए ओली ने कहा कि इटली ने भी हाल ही में अनियमित तरीके से कारोबार करने और मानहानि के मामले में मेटा पर अरबों रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा, 'जब यहां कंपनियां नियमों का पालन करने से इनकार करती हैं और कहती हैं कि वे राज्य या कानून को नहीं मानतीं। जब वे कहती हैं कि हम आपके संविधान और सरकार को नहीं मानते, तब हमने उन्हें बंद करने का फैसला किया था। इसके बावजूद मानवाधिकार आयोग का निष्कर्ष है कि विदेशी कंपनियों को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाले तत्कालीन संचार मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।'

ट्रंप के फिलीपींस पहुंचने से पहले अमेरिकी एआई परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन

मनीला,एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिलीपींस यात्रा से पहले देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इन प्रदर्शनों की मुख्य वजह मनीला के उत्तर में प्रस्तावित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और औद्योगिक केंद्र है। स्थानीय लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी जमीन, आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंच सकता है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह परियोजना अमेरिका की अगुवाई वाली अंतरराष्ट्रीय पहल 'पैक्स सिलिका' का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और आधुनिक तकनीक से जुड़े उद्योगों के लिए दूसरे देशों में मजबूत आपूर्ति व्यवस्था तैयार करना है। इसके तहत फिलीपींस में 4,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र बनाने की योजना है।

सोमवार को मनीला में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 'ट्रंप वापस जाओ' जैसे नारे लिखे पोस्टर और बैनर लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे का विरोध किया। कुछ पोस्टरों में ट्रंप को जोकर और शैतान के रूप में भी दिखाया गया। लोगों ने पैक्स सिलिका परियोजना को खारिज करने की मांग की। इस परियोजना के विरोधियों का कहना है कि औद्योगिक केंद्र बनने से किसानों और वहां रहने वाले आदिवासी एटा समुदाय को अपनी जमीन छोड़नी पड़ सकती है। इससे इलाके की जलापूर्ति पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह परियोजना फिलीपींस में अमेरिकी दबदबा बढ़ाने की कोशिश है। एटा समुदाय के बीच काम करने वाले शिक्षक और वकील मैनिंगिंग विलोग ने कहा, 'वे हमारी जमीन छीन रहे हैं। वे हमारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। पैक्स सिलिका केवल अमेरिका के हित में है, हमारे लिए नहीं।' प्रदर्शन में शामिल 20 वर्षीय कैसर कॉर्टिना ने भी परियोजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए एआई से ज्यादा जरूरी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। किसानों, पानी और सिगरेट बेचकर गुजारा करने वालों तथा बस चलाने वालों को एआई से क्या लेना-देना है? दूसरी ओर, फिलीपींस



के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर इस परियोजना का समर्थन कर रहे हैं। अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि इस योजना से देश को आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिल सकता है। उनके मुताबिक, इससे फिलीपींस को आधुनिक तकनीक से जुड़े उद्योगों और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मार्कोस सरकार का दावा है कि इस परियोजना से देश में एक लाख से लेकर एक लाख 30 हजार तक रोजगार पैदा हो सकते हैं।

क्या है पैक्स सिलिका पहल?

अमेरिकी विदेश विभाग ने दिसंबर 2025 में पैक्स सिलिका पहल की घोषणा की थी। इसके बाद 25 से अधिक देश इस पहल से जुड़ चुके हैं। इनमें ब्रिटेन, इजराइल, जापान और भारत भी शामिल हैं। फिलीपींस ने अप्रैल में इस पहल पर सहमति जताई थी। इसके बाद वहां औद्योगिक केंद्र बनाने की योजना सामने आई। अमेरिका लंबे समय से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जरूरी उपकरणों और सेमीकंडक्टर चिप की आपूर्ति को लेकर चिंतित रहा है। उसकी चिंता है कि चीन को अत्याधुनिक चिप हासिल करने का मौका मिल सकता है। इसी वजह से अमेरिका ऐसे देशों के साथ औद्योगिक सहयोग बढ़ाना चाहता है, जो इस क्षेत्र में चीन पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकें। हाल में यह मुद्दा फिर चर्चा में आया है। खबरों के अनुसार, एनवीडिया के पूर्व प्रमुख जेन्सेन हुआंग के संबंध एक ऐसी कारोबारी महिला से सामने आए हैं, जिस पर चीन की खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का संदेह है। उसकी कंपनी की चिप की तस्करी के आरोपों में जांच की जा रही थी। हालांकि, संबंधित कंपनी ने चिप की तस्करी के आरोपों से इनकार किया है। रविवार को पैक्स सिलिका से जुड़े देशों ने एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी आपूर्ति व्यवस्था, संवेदनशील तकनीक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लेकर साझा समझ विकसित करने की बात कही गई है। अमेरिकी और फिलीपींस के अधिकारियों के मुताबिक, इस सप्ताह मनीला में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप की यात्रा में पैक्स सिलिका को लेकर किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद नहीं है। ट्रंप के बुधवार को फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस से मुलाकात करने की संभावना है। इसके बाद वह चीन के लिए रवाना होंगे। सीबीएस न्यूज ने इस मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग से भी प्रतिक्रिया मांगी है। फिलीपींस की संसद के निचले सदन के सदस्य एंटोनियो टिनियो ने कहा कि पैक्स सिलिका को लेकर संसद में किसी विशेष मतदान की योजना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी यह तय नहीं है कि प्रस्तावित औद्योगिक केंद्र का निर्माण शुरू हो पाएगा या परियोजना सफल होगी। टिनियो के अनुसार, मनीला में इस परियोजना का विरोध केवल फिलीपींस तक सीमित नहीं है। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में एआई डेटा केंद्रों के निर्माण का विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा, 'एआई डेटा केंद्रों का विरोध दुनिया भर में हो रहा है। अमेरिका के चुनाव में भी यह एक बड़ा मुद्दा था। मलेशिया और इंडोनेशिया सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में भी इसका विरोध हो रहा है। फिलीपींस भी इससे अछूता नहीं है।

डोनाल्ड ट्रंप एशिया के दौरे पर निकले

द मनीला टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को एशिया के दौरे पर निकले हैं। इस दौरान उनका मुख्य ध्यान आर्थिक समझौतों और रूस तथा चीन के साथ होने वाली ऐतिहासिक त्रिपक्षीय परमाणु वार्ता पर रहेगा, जबकि वाशिंगटन में उनका प्रशासन नई राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। एयर फोर्स वन में सवार होने से पहले उन्होंने कहा कि चीन में उनकी मुलाकात किम जोंग उन से हो सकती है, क्योंकि अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से बातचीत शुरू करना चाहता है। ट्रंप के आज मनीला पहुंचने की संभावना है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली अपनी अहम बैठक में वह यूक्रेन में रूस के लगभग 5 साल से चल रहे युद्ध के बारे में भी बात करेंगे। एशिया के लिए रवाना होने से पहले सोमवार सुबह व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'हम मेरे पसंदीदा विषय, यूक्रेन के बारे में बात करेंगे। यूक्रेन अपना ही देश खो रहा है।' उन्होंने कहा, 'रूस के हर महीने 25,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। इसलिए हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे।'

नेपाल को भारत से 350 मेगावाट बिजली आयात की अनुमति, 56 मेगावाट निर्यात भी करेगा

काठमांडू। नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष सर्दियों के दौरान भारत से 350 मेगावाट बिजली आयात करने की अनुमति मिल गई है। भारत के विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (इंश्वङ्ग) के डे-अहेड और रियल-टाइम बाजार से प्रतिस्पर्धी दरों पर प्रतिदिन 17 घंटे तक बिजली खरीदने की अनुमति दी है। नेपाल को 17 नवंबर 2026 से 31 जुलाई 2027 तक बिजली आयात करने की अनुमति मिली है। इसके तहत सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक के समय को छोड़कर अन्य समय में इंश्वङ्ग के माध्यम से प्रतिदिन बिजली खरीदी जा सकेगी।

अनुमति के अनुसार, कटैया-कुशाहा, रामनगर-सुरजपुरा और रक्सौल-परवानीपुर 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से 300 मेगावाट तथा न्यू नौतनिया-मैनहिया 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के जरिए 50 मेगावाट बिजली आयात की जा सकेगी। इस तरह कुल 350 मेगावाट बिजली भारत से खरीदी जा सकेगी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक दीर्घायु श्रेष्ठ ने बताया कि भारत से 350 मेगावाट बिजली आयात की अनुमति मिलने से आगामी सर्दियों में बिजली की मांग और आपूर्ति का प्रबंधन करना आसान होगा। उन्होंने बताया कि रसुवा जिले में भोटेकोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के कारण जलविद्युत परियोजनाओं और ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते 431 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाएं राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली से कट गई हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगामी सर्दियों में बिजली की मांग और आपूर्ति के प्रबंधन के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं। पिछले वर्ष बिजली की मांग और उत्पादन की स्थिति के आधार पर किए गए विश्लेषण के अनुसार, इस वर्ष लगातार चार महीनों तक नेपाल में बिजली की मांग घरेलू उत्पादन से अधिक रहने का अनुमान है। इस अवधि में भारत से बिजली आयात करने की जरूरत पड़ेगी। विशेष रूप से फरवरी और मार्च महीने में प्रतिदिन औसतन 450 से 500 मेगावाट बिजली लगातार आयात करनी पड़ सकती है। वहीं, अधिक मांग वाले पीक आवर में प्रतिदिन 800 से 900 मेगावाट तक बिजली आयात करने की आवश्यकता का अनुमान है।

पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को मानहानि का नोटिस, सालिक हुसैन ने लगाए गंभीर आरोप

इस्लामाबाद,एजेंसी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (कायद-ए-आजम) के नेता चौधरी सालिक हुसैन ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को मानहानि का नोटिस भेजा है। हुसैन ने सोमवार को यह जानकारी दी। पीएमएल-क्यू नेता सालिक हुसैन ने इससे पहले पंजाब सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री मरियम ने उन्हें पांच अरब रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा था। नोटिस में सालिक से अपने बयान को वापस लेने की मांग की गई थी। चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट में प्रवासी पाकिस्तानी और मानव संसाधन विकासमंत्री हैं।



डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पीएमएल-क्यू नेता सालिक हुसैन ने बताया कि उन्होंने मरियम के नोटिस का जवाब देने के साथ-साथ दो नोटिस भी भेजे हैं। उन्होंने कहा कि मरियम और पंजाब की सूचनामंत्री अज़मा बुखारी को भी मानहानि के दो कानूनी नोटिस भेजे हैं। सालिक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कानूनी नोटिस का औपचारिक जवाब भेज दिया गया है।' उन्होंने फिर दोहराया, 'कानूनी नोटिस के जरिए डराने-धमकाने की कोशिशें मुझे चुप नहीं करा सकतीं और न ही मुझे जनहित और लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों को उठाने से रोक सकती हैं। उन्होंने ने अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा, 'यह प्रांत भारी कुप्रबंधन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। ऐसे मुद्दों पर डराने-धमकाने के बजाय, थोड़ी आत्म-समीक्षा और जवाबदेही की जरूरत है।' पीएमएल-क्यू नेता ने 'पंजाब और पाकिस्तान के हित में पारदर्शिता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता' को भी दोहराया। एक्स पर एक अलग पोस्ट में सालिक ने बताया, 'इसके अलावा, मैंने अपने कानूनी सलाहकार के जरिए मानहानि के दो कानूनी नोटिस भेजे हैं। एक नोटिस मरियम नवाज शरीफ को और दूसरा अजमा जाहिद बुखारी को भेजा गया है। पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में सालिक ने कहा कि वह पंजाब में भ्रष्टाचार को लेकर अपनी पिछली बातों पर कायम हैं। उन्होंने मरियम के बयानों को 'अनुचित और निचले स्तर का' बताया। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि अजमा बुखारी के तीखे बयानों ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। सालिक की ओर से वकील वलीद खालिद के जरिए मरियम को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस 3 नवंबर, 2026 को अटक में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान मरियम द्वारा दिए गए 'झूठे, बेबुनियाद और मानहानि करने वाले' बयानों के संबंध में भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि ये बयान किसी की प्रतिष्ठा पर 'अनुचित हमला' है और इन्हें बिना किसी कानूनी आधार के दिया और फैलाया गया है। इसमें 'पंजाब मानहानि अधिनियम 2024' की धारा 2(द्ध) और 3 का हवाला दिया गया है। नोटिस में मांग की गई है कि इसे मिलने के सात दिनों के भीतर मरियम सालिक पर लगाए गए आरोपों को वापस लें और 'बिना शर्त माफी' मांगें। यह माफी उसी तरह प्रमुखता से दी जानी चाहिए, जिस तरह से उनके मूल बयान प्रकाशित या प्रसारित किए गए थे।

बांग्लादेश के कारोबारी दहशत में, रंगदारी न मिलने पर अपराधी कर रहे खूनखराबा

ढाका,एजेंसी। बांग्लादेश के व्यापारी दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं। अपराधी रंगदारी न मिलने पर खूनखराबा कर रहे हैं। रविवार को भी राजधानी ढाका के कुछ और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। मोहम्मदपुर और हजारीबाग में 'एजेआर कूरियर सर्विस' के वाहनों और एक गोदाम पर हमला किया गया। रामपुरा में एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के दफ्तर में दो लोगों को गोली मार दी गई। पुलिस और अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने राजधानी में 545 रंगदारों और अपराधियों की सूची के आधार पर धरपकड़ तेज कर दी है। फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि गिरफ्तारियों के बावजूद रंगदारों का हथियारों के दम पर दबदबा क्यों खत्म नहीं हो रहा है?

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 11 बजे का समय रहा होगा। राजधानी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज के सामने और श्यामोली की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे स्थित अनुराग फार्मेसी में कर्मचारी मोइनउद्दीन ग्राहकों को सेवा दे रहे थे। अचानक, गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही गोलियों का दूसरा दौर चला। गोलियां फार्मेसी के शीशे को तोड़ते हुए मोइनउद्दीन के सिर के ऊपर से निकल गईं। वह बाल-बाल बच गए। आरोप है कि शूटर बादल और शूटर पप्पू नाम के दो अपराधियों ने फार्मेसी के



मालिक से 50 लाख टका की रंगदारी मांगी थी। पैसे न मिलने पर उन्होंने पहले दो देसी बम फेंके। इसके बाद उन्होंने सीधे फायरिंग कर दी। सिर्फ अनुराग फार्मेसी ही नहीं, बल्कि राजधानी के कई हिस्सों में रंगदारी की मांग को लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर फायरिंग, हमले, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। रविवार को मोहम्मदपुर और हजारीबाग में एजेआर कूरियर सर्विस के वाहनों और एक गोदाम पर हमला किया गया। उसी शाम रामपुरा में एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के दफ्तर में दो लोगों को गोली मार दी गई। एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं से कारोबारियों के बीच चिंता बढ़ रही है। आरोप है कि अपराधी पहले फोन पर कारोबारियों को धमकी देकर उनसे रंगदारी मांगते हैं। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तो वे खूनखराबा करदहशत फैलाते हैं। ऐसे हालात में, कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने राजधानी में 545 रंगदारी वसूलने वालों और अपराधियों की एक सूची के आधार पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। अनुराग फार्मेसी के एक रेस्तरां और एक सुपरशॉप को भी निशाना बनाया गया है। इन प्रतिष्ठानों के मालिक सैयद हसन नूर इस्लाम हैं। वे पूर्व पार्षद और अवामी लीग के नेता के रूप में जाने जाते हैं। पता चला है कि 5 अगस्त, 2024 को हुए राजनीतिक बदलाव के बाद से वे देश से बाहर हैं। सूत्रों के अनुसार मोहम्मदपुर इलाके के दो अपराधियों बादल और पप्पू ने हाल ही में उनसे 50 लाख टका की रंगदारी मांगी थी। पैसे न मिलने पर उन्होंने बम और गोली चलाकर दहशत फैलाई। पुलिस ने बताया कि फार्मेसी में हुई गोलीबारी के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमले में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। राजधानी के रामपुरा और हातिरझील इलाकों में रंगदारी मांगने के आरोपों को लेकर गुजा बादशाह नाम का एक अपराधी चर्चा में है।

बहरीन के ईसा एयरबेस पर ईरान का ड्रोन हमला, अमेरिकी रडार सिस्टम निशाने पर, वाशिंगटन में सैन्य हलचल तेज

मनामा/वाशिंगटन/तेहरान। बहरीन के ईसा एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद अमेरिका में सैन्य हलचल तेज हो गई है। खाड़ी देश के सरकारी टेलीविजन का दावा है कि बहरीन ने हमले को विफल कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने मंगलवार को दावा किया कि उसने बहरीन के ईसा एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम पर ड्रोन से हमला किया। अल जजीरा की रिपोर्ट में ईरान के प्रसारक आईआरआईबी के हवाले से बताया गया है कि आईआरजीसी ने बहरीन में अमेरिकी सेना की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को जवाब दिया है। कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में खाड़ी देश में अमेरिकी रडार सिस्टम पर यह सबसे ताजा हमला है। इस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कुछ नव-रूढ़िवादी युद्ध को जारी रखना चाहते हैं।

बहरीन की राजधानी मनामा में मंगलवार को धमाकों की आवाज सुनी गई है। इससे पहले वहां के निवासियों को उनके मोबाइल फोन पर एक अलर्ट मिला, जिसमें संभावित खतरे की चेतावनी दी गई। गृह मंत्रालय के इस अलर्ट में लोगों से सबसे नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया। इसके कुछ देर बाद ही धमाके सुनाई दिए। वाशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, बहरीन को सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य में नौसैनिक बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद चार टैंकरों में आग लग गई। वहीं, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दावा है कि उसने ईरान के केशम द्वीप के पास उड़ रहे एक अमेरिकी ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। बहरीन में हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए की जा रही राजनयिक कोशिशें रुकी हुई हैं। यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था और इसने पूरे खाड़ी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों को प्रभावित किया है। गल्फ डेली न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से संबंध रखने के दोषी पाए गए लोगों के एक समूह को 15 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई है। हाई क्रिमिनल कोर्ट ने इनमें से कुछ पर 1-1 लाख बहरीनी दीनार का जुर्माना भी लगाया है और 80 लाख बहरीनी दीनार जब्त करने का आदेश दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, सात अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि नई अमेरिकी खुफिया जानकारी सामने आने के बाद वाशिंगटन में सैन्य हलचल तेज हो गई। खुफिया जानकारी में बताया गया है कि ईरान वाशिंगटन डीसी में डर्टी बम या रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करके ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। हालांकि, अधिकारी अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या ईरान वास्तव में ऐसी साजिश को अंजाम दे सकता है या ऐसा करने की कोशिश करेगा।

एक नजर

त्योहारी सीजन में उत्तर रेलवे ने 1.82 करोड़ यात्रियों को कराई सुरक्षित यात्रा

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने इस बार व्यापक स्तर पर इंतजाम किए। पूजा और त्योहारों के दौरान उत्तर रेलवे ने करीब 1.82 करोड़ यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के 1.72 करोड़ यात्रियों की तुलना में करीब 10 लाख अधिक है। उत्तर रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, वर्ष 2026 के त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाने, नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने और यात्री मांग की लगातार निगरानी करने जैसे कदम उठाए गए। त्योहारी सीजन के दौरान उत्तर रेलवे और अन्य समन्वयक क्षेत्रीय रेलों ने कुल 7,085 विशेष ट्रेन फेरे संचालित किए, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 4,666 थी। इस प्रकार विशेष ट्रेनों के संचालन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिदिन औसतन करीब 54 अतिरिक्त विशेष ट्रेन फेरे चलाए गए। उत्तर रेलवे में दैनिक यात्री संख्या भी बढ़कर 4.14 लाख हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा करीब 3.91 लाख था। इस तरह प्रतिदिन लगभग 22,700 अतिरिक्त यात्रियों को रेल यात्रा की सुविधा मिली। कुल 1.82 करोड़ यात्रियों में से करीब 1.66 करोड़ यात्रियों ने नियमित ट्रेनों से सफर किया, जबकि 12.83 लाख यात्रियों ने विशेष ट्रेन ऑन डिमांड (टीओडी) सेवाओं का लाभ उठाया। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने नियमित ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच लगाए। इस वर्ष त्योहारी अवधि में कुल 581 अतिरिक्त कोच जोड़े गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 123 कोच लगाए गए थे। इस तरह अतिरिक्त कोच लगाने की संख्या में करीब 372 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि विशेष ट्रेनों के संचालन, नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने और यात्रियों की मांग की रियल टाइम निगरानी के जरिए त्योहारी भीड़ का प्रभावी प्रबंधन किया गया। इन प्रयासों से लाखों यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध कराई जा सकी।

जमात-ए-इस्लामी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीनियों की संप्रभुता के समर्थन में भारत के वोट का स्वागत किया

नई दिल्ली। जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने 11 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव के पक्ष में भारत के वोट का स्वागत किया है। प्रस्ताव में फलस्तीनी लोगों के अपने प्राकृतिक संसाधनों भूमि, जल और ऊर्जा पर उनके अधिकारों की पुन: पुष्टि की गई है। मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत का वोट एक स्वागतयोग्य कदम है। यह एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के समर्थन में भारत के ऐतिहासिक रुख और अन्याय के खिलाफ उसके विरोध को दर्शाता है। गौरतलब है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 150 अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया जबकि इज़राइल और अमेरिका उन सात देशों में शामिल थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष ने कहा कि एक ऐसे समय में जब भारत को इज़राइल के साथ और फलस्तीन के दुश्मन के रूप में पेश करने की कोशिशें हो रही हैं, यह ज़रूरी है कि फलस्तीनी लोगों के जायज़ अधिकारों के लिए भारत के समर्थन को पहचाना जाए और इसकी सराहना की जाए। फलस्तीन का समर्थन करना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भारत के राष्ट्रीय हित में है।

उन्होंने आगे कहा कि इस प्रस्ताव में फलस्तीनी लोगों के उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों की फिर से पुष्टि की गई है। साथ ही इज़राइल से अंतरराष्ट्रीय कानून – जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून भी शामिल है, के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में इज़राइली बस्तियां और वहां बनाई जा रही दीवार अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। यह चीजें फलस्तीनी लोगों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से गंभीर रूप से वंचित करती हैं। इस प्रस्ताव में पानी की पाइपलाइनों, सीवेज नेटवर्क और बिजली नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं को नष्ट करने तथा फलस्तीनी घरों, नागरिक बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और पानी के कुओं को ढहाने और जब्त करने की कार्रवाई को समाप्त करने की भी मांग की गई है। जमात के अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में अपना रुख क़ायम रखा है और हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार हासिल करेगी ऐतिहासिक विजय: नितिन नवीन



लखनऊ,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दो दिवसीय योजना बैठक मंगलवार को मथुरा के परखम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो-विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुई। समापन सत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदाधिकारियों को आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 'मिशन-2027' की तैयारियों का मंत्र दिया। नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी के समर्पित एवं अथक परिश्रमी कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक विजय दर्ज करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने तथा सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यूपी में डबल इंजन वाली योगी सरकार ने विकास को घर—घर पहुंचाया है। बैठक में नितिन नवीन ने आगामी तीन महीनों की कार्ययोजना, संगठनात्मक गतिविधियों और सहयोगी दलों के साथ समन्वय पर विस्तृत चर्चा की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी चुनाव में किसी भी विपक्षी दल को सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चिह्नित चार प्रमुख श्रेणियों महिला, गरीब, युवा और किसान के सशक्तिकरण और सरकारी उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच जाएगी। मथुरा पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक ने स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष स्व. अशोक सिंघल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी.एल. संतोष, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

गोपाष्टमी भारतीय आस्था, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा पर्व: राज्यपाल

रांची,एजेंसी। रांची के हरमू रोड स्थित गोकुल धाम में मंगलवार को आयोजित श्री कृष्ण गोपाष्टमी महोत्सव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रांची गौशाला न्यास की ओर से गौ-सेवा, पशु संरक्षण और समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोपाष्टमी भारतीय आस्था, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा पर्व है। भगवान श्रीकृष्ण का जीवन सभी जीवों के प्रति प्रेम, दया और संवेदनशीलता रखने की प्रेरणा देता है। गौ-सेवा के माध्यम से समाज में करुणा और सेवा का भाव मजबूत होता है।

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय को सेवा, करुणा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी गौवंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गौ-संरक्षण के साथ पर्यावरण की रक्षा और टिकाऊ विकास को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1904 में स्थापित रांची गौशाला न्यास पिछले 122 वर्षों से गौ-सेवा और सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है। वर्तमान में गोकुल धाम में लगभग 1100 गौवंश का पालन-पोषण और संरक्षण किया जा रहा है। इनमें बड़ी संख्या में ऐसी गायें भी हैं, जो दूध नहीं देती हैं। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे गौवंश की देखभाल करना संवेदना, सेवा और मानवीय मूल्यों का उदाहरण है। उन्होंने न्यास के पदाधिकारियों, सदस्यों और सेवा कार्यों से जुड़े लोगों के प्रयासों की प्रशंसा की। राज्यपाल ने गौशाला में गोबर से जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने की पहल को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलती है। वर्तमान समय में पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाना जरूरी है। ऐसे प्रयास किसानों और समाज, दोनों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। गोकुल धाम परिसर में संचालित अन्नपूर्णा सेवा प्रकल्प की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मात्र 10 रुपये में छह रोटी, सब्जी और अचार उपलब्ध कराना जरूरतमंद लोगों की सेवा का सराहनीय प्रयास है। यह पहल दिखाती है कि गौशाला न्यास का कार्य केवल पशुओं की देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने जैसे सामाजिक कार्य भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गौ-सेवा को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं समझना चाहिए। यह जीवों के प्रति जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और सामाजिक चेतना से भी जुड़ी है।

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखण्डियों से अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहने का किया आह्वान

लखनऊ,एजेंसी। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन, लखनऊ में उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड महोत्सव 2026 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपनी संस्कृति, परंपराओं, लोकभाषा और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और विशिष्ट जीवनशैली में निहित है। भौगोलिक रूप से हम कहीं भी रहें, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी बोली-भाषा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जुड़ाव सदैव बनाए रखना चाहिए।

अपनी जड़ों से जुड़कर रहना हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी पहचान और विरासत से परिचित कराने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन सम्मेलनों के माध्यम से देश-विदेश में रह रहे उत्तराखण्ड के प्रवासियों को एक मंच पर लाकर उनके अनुभवों, ज्ञान, कौशल, निवेश और सामर्थ्य का लाभ प्रदेश के विकास में लेने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य की अमूल्य धरोहर हैं। वे जहां भी रहते हैं, अपनी मेहनत, प्रतिभा और कार्यकुशलता से उत्तराखण्ड का नाम रोशन करते हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे अपने गांवों, स्थानीय उत्पादों, पर्यटन स्थलों और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास में भी योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के आपसी संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हमारा सहोदर भाई है। दोनों राज्यों के बीच केवल भौगोलिक और प्रशासनिक संबंध ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड की प्रगति एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में सड़क, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास, पर्यटन, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

आईसीएआर और आरआईएस ने आदान-प्रदान को सुदृढ़ बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) ने मंगलवार को नई दिल्ली में विकासशील देशों के बीच कृषि सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव तथा आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट और आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा के बीच किया गया। दक्षिण-ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से सुगम बनाई गई यह साझेदारी कृषि प्रौद्योगिकियों को साझा करने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का प्रलेखन करने, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता विकास पर केंद्रित होगी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 'विकासशील देश: एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर' विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय नीति संवाद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इस बात पर बल दिया कि विकासशील देशों को वैश्विक विमर्श को आकार देने, आर्थिक गतिशीलता विकसित करने और विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में अपनी सामूहिक आवाज को सुदृढ़ करना चाहिए। उन्होंने भारत-अफ्रीका साझेदारी को और मजबूत बनाने, संस्थागत सहयोग बढ़ाने तथा ज्ञान को सार्थक नीतिगत परिणामों में बदलने के लिए युवा शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी की अपील की।

विदेश राज्य मंत्री ने नवंबर 2023 में आयोजित दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को याद करते हुए साझा चुनौतियों पर समान दृष्टिकोण विकसित



करने, आर्थिक गतिशीलता को मजबूत करने तथा किफायती, व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास समाधानों को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने पारंपरिक विकास सहयोग से आगे बढ़कर सह-विकास और साझा समाधानों की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। डीएआरई के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट ने कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में एक शताब्दी पुराने शीर्ष संस्थान के रूप में आईसीएआर की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आईसीएआर के अंतर्गत 114 अनुसंधान संस्थान, 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) कार्यरत हैं, जबकि यह लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करता है। उन्होंने बताया कि आईसीएआर ने विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ 74 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत समझौते विकासशील देशों के संस्थानों के साथ किए गए हैं। डॉ. जाट ने इस बात पर जोर दिया कि आरआईएस और 'दक्षिण' के साथ साझेदारी विभिन्न देशों के बीच उपलब्ध कृषि प्रौद्योगिकियों, कार्यप्रणालियों, प्रणालियों, विधियों और उपकरणों के आदान-प्रदान एवं उनके उपयोग को सुगम बनाकर विकासशील देशों के बीच सहयोग को और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने देशों को आपस में जोड़ने के लिए उपयुक्त कृषि-जलवायु और अनुसंधान के कार्यक्षेत्रों की पहचान करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अप्रैल 2027 के मध्य में प्रस्तावित विज्ञान एवं साझेदारी सप्ताह का भी उल्लेख किया, जिसमें विकासशील और विकसित देशों के प्रतिभागी भारत में एकत्रित होंगे। इसके साथ ही, उन्होंने मांग आधारित साझेदारी के माध्यम से विकासशील और विकसित देशों के नेताओं को एक मंच पर लाने के विचार का उल्लेख किया, ताकि वे अपनी-अपनी आवश्यकताओं और उपलब्ध क्षमताओं पर चर्चा कर सकें।

34 साल बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : पांच साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी की फांसी बरकरार



कोलकाता,एजेंसी। धनंजय चटर्जी मामले के 34 साल बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) ने एक बार फिर दुष्कर्म और हत्या के एक जघन्य मामले में मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की है। मंगलवार को हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने हुगली जिले के गुड़ाप में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ हुए क्रूर दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी अशोक सिंह की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि, दोषी को सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में अपनी अपील दायर करने का कानूनी अवसर प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट ने अगले तीन महीने तक इस सजा पर अमल को स्थगित रखने का निर्देश दिया है।

इससे पहले, हुगली के चिनसुरा (चूंचुड़ा) स्थित निचली अदालत ने दोषी अशोक सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपित ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंगलवार को न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा की खंडपीठ ने मामले की गहन सुनवाई के बाद निचली अदालत के मृत्युदंड के फैसले को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखा। यह फैसला ऐतिहासिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि साल 1990 (बाद में 1992 में पुष्टि) में कलकत्ता हाईकोर्ट ने धनंजय चटर्जी (हेतल पारेख दुष्कर्म-हत्या मामला) को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2004 में फांसी दी गई थी। उसके बाद, पिछले 34 वर्षों में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा किसी मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने का यह पहला बड़ा मामला है। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पिछले साल 24 नवंबर की शाम की है। हुगली जिले के गुड़ाप इलाके में पांच साल की एक मासूम बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी। बच्ची के पिता ने उसे आखिरी बार तब देखा था जब वह बाजार जा रहे थे। जब पिता बाजार से लौटे तो उन्होंने देखा कि बेटी लापता है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने बच्ची की काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद, पड़ोस में ही रहने वाले अशोक सिंह के घर से बच्ची का शव बरामद हुआ। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपित अशोक सिंह की जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने तुरंत मामले में पॉक्सो दुष्कर्म और हत्या के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली और अदालत की सुनवाई बेहद तेज रही। पुलिस ने घटना के मात्र 15 दिन बाद नौ दिसंबर को चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर दी। 11 दिसंबर को आरोपित के खिलाफ आरोप तय किए गए। अदालत ने इस संवेदनशील मामले की तेजी से सुनवाई (फास्ट ट्रैक) करते हुए कुल 27 गवाहों के बयान दर्ज किए और लगभग एक महीने के भीतर पूरी न्यायिक प्रक्रिया को संपन्न कर दिया। चिनसुरा की पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश चंद्रप्रभा चक्रवर्ती ने तमाम साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अशोक सिंह को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि जिस दिन अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, संयोग से उसी दिन पीड़ित मासूम बच्ची का जन्मदिन भी था। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस सजा पर अपनी मुहर लगा दी है, जिससे न्याय की उम्मीद और पुख्ता हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए दी गई तीन महीने की मोहलत के कारण फिलहाल सजा के अमल (फांसी) पर रोक रहेगी।

भाजपा सभी वर्गों तक पहुंचाएगी चुनावी संदेश, 70 महिला विधानसभा विस्तारक भी होंगी नियुक्त

देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए अपने मोर्चों एवं प्रकोष्ठों को सक्रिय करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत पार्टी कॉर्नर मीटिंग, ड्राइंग रूम मीटिंग, किसान चौपाल, मोटरसाइकिल रैली और विधानसभा स्तर पर वर्ग विशेष सम्मेलनों के माध्यम से जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसके साथ ही पार्टी सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में महिला विस्तारकों की नियुक्ति भी करने जा रही है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को मीडिया से बातचीत में प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों और क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत युवा मोर्चा प्रदेश के 3,032 शक्ति केंद्रों पर एक-एक कॉर्नर मीटिंग आयोजित करेगा। इसके अलावा विधानसभा स्तर पर मोटरसाइकिल रैलियां निकालने के साथ महाविद्यालयों, कोचिंग सेंटरों और अन्य स्थानों पर युवाओं से संपर्क किया जाएगा। विधानसभा स्तर पर युवा सम्मेलन भी आयोजित होंगे।

मोर्चों और प्रकोष्ठों को सौंपी जनसंपर्क की जिम्मेदारी, कॉर्नर मीटिंग, किसान चौपाल और वर्ग विशेष सम्मेलनों के जरिए साधेगी मतदाता

उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा प्रदेश के सभी 12,543 बूथों पर ड्राइंग रूम मीटिंग आयोजित करेगा। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के साथ संपर्क और विधानसभा स्तर पर महिला सम्मेलन किए जाएंगे। किसान मोर्चा प्रदेश के सभी 304 मंडलों में किसान चौपाल लगाएगा। वहीं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मोर्चा अपने-अपने समाज के बीच विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित करेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्धजनों के बड़े सम्मेलन भी प्रस्तावित हैं।

परिहार ने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी का प्रयास मुख्य संगठन के साथ-साथ मोर्चों और प्रकोष्ठों के सहयोग से समाज के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र तक पहुंचना है। इन गतिविधियों से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। वहीं,प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने बताया कि भाजपा अपनी विस्तारक योजना के तहत सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति कर चुकी है। इसी क्रम में अब 70 महिला विस्तारक भी नियुक्त की जाएंगी। ये प्रवासी महिला कार्यकर्ता संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में रहकर पार्टी के कार्यक्रमों को महिलाओं और मातृशक्ति के बीच पहुंचाएंगी। बंसल ने कहा कि पार्टी की सफलता में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके सहयोग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए 65 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाई गई रणनीति में महिला विस्तारकों की नियुक्ति भी अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ पार्टी विभिन्न मोर्चों के माध्यम से अलग-अलग वर्गों तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। सरकार की ओर से दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाए गए विकास कार्यों को आधार बनाकर पार्टी जनता के बीच समर्थन जुटाएगी।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)